हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 308 बेमेतरा, शनिवार 04 जुलाई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

दो करोड़ लोग, 30 देशों के प्रतिनिधि कर रहें है

तीन महीने बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम विदाई शुरू

ईरान/ एजेंसी

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू होगी और उनके गृहनगर पवित्र शहर मशाद में नौ जुलाई को दफ्नाने के साथ खत्म होगी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान करीब दो करोड़ लोग वहां मौजूद होंगे, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह सबकुछ छह दिन तक चलेगा। अंतिम संस्कार की रस्में, दक्षिणी तेहरान के पवित्र शहर कौम में भी होंगी। बता दें कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के दौरान खामेनेई की मौत हो गई थी। दोनों देशों के बीच फिलहाल शांति बहाल है और युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में, 4 जुलाई से शुरू होंगी। इस दिन खामेनेई का ताबूत तेहरान के 'ग्रैंड मोसल्ला' में रखा जाएगा। इस दौरान ईरान की आम जनता, उनके दर्शन करेगी। इसके बाद छह जुलाई को तेहरान की गलियों में खामेनेई की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा इस दिन पवित्र शहर कौम पहुंचेगी। यह शहर तेहरान के दक्षिण-पश्चिम में करीब 140 किमी दूर है। कौम शहर, शिया इस्लामिक विद्वानों का एक अहम सेंटर माना जाता है। इसके बाद अंतिम यात्रा पहुंचेगी दो अन्य ऐतिहासिक और पवित्र शहरों, नजफऔर कर्बला में। यह दोनों शहर इराक के पड़ोस में हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का यह अंतिम दिन

होगा। इस दिन उन्हें मशाद के इमाम रेजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। यह खामेनेई का गृहनगर भी है। ईरान के सरकारी मीडिया द्वारा जारी वीडियो में गुरुवार रात खामेनेई के लिए आयोजित एक शोकसभा दिखाई गई। काले कपड़े पहने शोकाकुल लोगों ने स्कार्फ और अन्य वस्तुएं वहां मौजूद सहायकों की ओर फेंकीं ताकि उन्हें ताबूत से स्पर्श कराया जा सके। ईरान में यह एक आम परंपरा है। ईरान की सरकारी मीडिया ने खामेनेई के ताबूत की तस्वीरें जारी कीं। इस पर लाल झंडा लिपटा हुआ था। इस झंडे पर सफेद अक्षरों में 'या हुसैन' लिखा था। यह शिया समुदाय का एक वाक्यांश है, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे की सातवीं सदी में हुई शहादत की याद दिलाता है। परंपरागत रूप से यह झंडा अन्यायपूर्ण तरीके से मारे गए व्यक्ति के बहाए गए खून और उसका बदला लेने के आह्वान का भी प्रतीक है। ईरान सरकार का आकलन है कि शनिवार से राजधानी की सड़कों पर करीब दो करोड़ लोग उतरेंगे। यह दृश्य 1989 में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रूहुल्ला खुमैनी के अंतिम संस्कार जैसा हो सकता है। इससे खासकर ऐसे समय में ईरान सरकार का मनोबल बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जब वह युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने नियंत्रण का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

खामेनेई के जनाजे में शामिल हुआ भारतीय डेलिगेशन, महबूबा मुफ्ती हुई भावुक

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंच गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तेहरान पहुंचकर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी, इस दौरान

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भावुक हो उठी। उन्होंने अली खामेनेई को लहरों के खिलाफलड़ने वाले मसीहा बताया। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत पर अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता दिखाने के लिए तेहरान में होना मेरे लिए सम्मान की बात है।

राम मंदिर मामले में

जेल जाएंगे चंपत राय अनिल मिश्रा-कटियार

नई दिल्ली/ एजेंसी

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बजरंग दल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफतौर पर कहा कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जेल जा सकते है। विनय कटियार पूर्व सांसद और राम मंदिर से जुड़े आंदोलनों में अपनी अहम भूमिका निभा चुके है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों पर कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। जो भी होगा, वह ठीक होगा। विनय कटियार ने आगे कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संपर्क में बने हुए हैं। उन्हें भरोसा है कि

सब ठीक हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर चंपत राय को आगे चलकर जेल भी जाना पड़ सकता है। राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित चोरी के मामले पर बीजेपी नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने कहा, यह साफहै कि पैसे का गबन हुआ है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जांजगीर-चांपा जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान सोठी स्थित भारतीय कुष्ठ निवारक संघ आश्रम पहुँचे। आश्रम आगमन पर संस्था के पदाधिकारियों एवं आश्रमवासियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने आश्रम प्रमुख सुधीर देव से संस्था की सेवा गतिविधियों, चिकित्सा सुविधाओं तथा पुनर्वास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा आश्रम द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की।

मोदी कैबिनेट में होने जा रहा है फेरबदल?

अमित शाह के आवास पर 3 घंटे चली बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोश के बीच गुरुवार को नितिन नवीन की बैठक हुई थी। तीन घंटे चली इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही टीम नवीन का ऐलान हो सकता है। गुरुवार को नितीन नवीन ने मुलाकात अमित शाह के आवास पर बीएल संतोष से मुलाकात की।इस मुलाकात में किसी फैसले की कोई आधिकारी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस दौरान नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम के गठन को लेकर मंथन किया गया है। इस बैठक के बाद कैबिनेट में बड़े

फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन यह साफ हो पाना बाकी है कि मंत्री पद से हटाकर संगठन में भेजा जाएगा या वे पद पर बने रहेंगे।

राम मंदिर मामले में कलयुग से ज्यादा छलयुग!

पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री बोले- मठ-मंदिरों को बना रहे निशाना

अयोध्या / एजेंसी

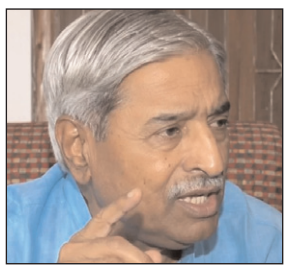

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अयोध्या दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमें देश की न्याय-व्यवस्था और सरकार पर पूरा भरोसा है और कहा कि सभी दोषियों को सजा मिलेगी। साथ ही, धीरेंद्र शास्त्री ने आरोप लगाया कि कुछ शक्तियां वर्तमान समय में संतों और मठ-मंदिरों के प्रति आस्था और श्रद्धा गिराने के मकसद से सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र कर रही हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन

किए। उन्होंने हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास के गुरु महंत संत राम दास के आश्रम पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हमने हनुमान गढ़ी में हनुमान दादा के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास के गुरु महंत संत राम दास का हाल ही में निधन हुआ। वे उज्जैनिया पट्टी के श्रीमहंत थे। उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अयोध्या आए हैं। यह हमारा सौभाग्य है। इसी दौरान, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, यह कोई मामूली पाप नहीं, बल्कि महापाप है और भगवान इसकी सजा देंगे। लेकिन हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमें देश के कानून-व्यवस्था और एसआईटी पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जांच चल रही है। हमें देश की न्याय-व्यवस्था और सरकार पर पूरा भरोसा है और सभी दोषियों को सजा मिलेगी। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, वर्तमान में कलयुग से ज्यादा छलयुग चल रहा है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला : आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी

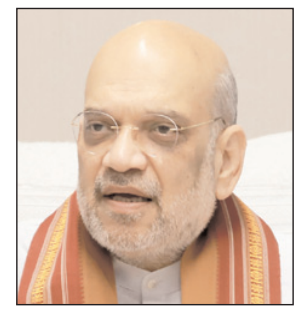

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भीतर भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहली बार ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर खुलकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जिम्मेदारी गोपाल राव की है और वे राजनीति कर रहे हैं। महंत दिनेंद्र दास ने कहा, पूरी गलती गोपाल राव की है। वे सभी को उलझा देते हैं और राम की परंपरा को नहीं मानते। गोपाल राव राम मंदिर निर्माण के प्रभारी और ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य रहे हैं। वे मूल रूप से कर्नाटक के निवासी हैं।

सीजेआई से इंडिया गठबंधन की ये कैसी गुहार

आपसे ही अंतिम आस,वरना ध्वस्त हो जाएगा लोकतंत्र....

नई दिल्ली/ एजेंसी

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने देश के मुख्य न्यायाधीशजस्टिस सूर्यकांत को लिखे अपने पत्र का पूरा टेक्स्ट शुक्रवार को जारी किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में हेर-फेर की जा रही है और चेतावनी दी गई है कि अगर न्यायपालिका ऐसी चिंताओं पर कोई कदम नहीं उठाती है, तो यह लोकतंत्र के पूरी तरह से ध्वस्त होने का संकेत होगा। विपक्षी गठबंधन ने इस पत्र में कहा है कि जब सभी संस्थागत तंत्र विफल हो जाते हैं तो नागरिकों

की अंतिम उम्मीद न्यायपालिका ही होती है। पिछले महीने की 28 जून को विपक्ष के 23 दलों के नेताओं ने यह पत्र लिखा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। छह पेज के इस पत्र में कहा गया है कि आम तौर पर वे चीफजस्टिस को पत्र नहीं लिखते। पत्र में कहा गया, क्योंकि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हमने यह असामान्य रास्ता चुना है। न्यायपालिका से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का आग्रह करते हुए विपक्ष ने पत्र में लिखा है, जब बाकी सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। इसलिए, जब न्यायपालिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, तो यह लोकतंत्र के पूरी तरह से विफल होने का संकेत है।

ओमप्रकाश जायसवाल बने हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार

17 जजों का ट्रांसफर-अजय संभालेंगे एनआईए कोर्ट की कमान

बिलासपुर/ संवाददाता

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के न्यायिक अधिकारियों को तबादला आदेश जारी किया है. इस आदेश में 17 उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को तबादला किया गया है.हाईकोर्ट से जारी आदेश में जगदलपुर में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत को स्पेशल जज एनआईए कोर्ट जगदलपुर में पदस्थ किया गया है. सिद्धार्थ अग्रवाल द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर, किरन कुमार जांगड़े को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर-रामानुजगंज, विनय कुमार प्रधान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ्टीसी पाक्सों रायपुर को रायपुर में ही एफ्टीसी कोर्ट में पदस्थ किया गया है. डमरूधर चौहान षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर को दसम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद रायपुर में ही पदस्थ किया गया है.इस प्रकार बलौदाबाजार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी का तबादला हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार विजलेंस के पद में किया गया है. बलौदाबाजार के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा का छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी बिलासपुर में एडिशनल डायरेक्टर के पद में तबादला किया गया. हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव ओम प्रकाश जायसवाल को हाईकोर्ट में ही रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पद में पदस्थ

किया गया है. रूपनारायण पात्रे द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर को हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी हाईकोर्ट में सचिव के पद में पदस्थ किया गया है. भौगोलिकसंदर्भविनिता वारनेर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर को बलौदाबाजार में पदस्थ किया गया. सूरजपुर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थामस एक्का को सूरजपुर में ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद में पदस्थ किया गया है. रायपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश एस्ट्रोसिटी कोर्ट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. विशेष न्यायाधीश एनआईए को जगदलपुर संगीता नवीन तिवारी का बलौदाबाजार में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर-रामानुजगंज डॉ.मनोज कुमार प्रजापति का सारंगढ़ रायगढ़, अमित राठौर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ का रायपुर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक सुमित कपूर का रायपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी के एडिशनल डायरेक्टर अमित कुमार कोहली को बलरामपुर-रामानुजगंज तबादला किया गया है. हाईकोर्ट के वेब साइड में तबादला आदेश जारी कर दिया गया है.

युक्तियुक्तकरण नीति पर हाईकोर्ट की मुहर, सरकार के निर्णय को ठहराया सही

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और शालाओं के युक्तियुक्तकरण की नीति पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है. इस नीति को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ सहित प्रदेशभर के शिक्षकों की सभी 24 से अधिक याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस बिभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा, कि शिक्षकों का स्कूलों में तर्कहीन या असमान वितरण सुधारने के लिए सरकार का यह कदम जनहित में है. डेमोग्राफ़िक्स बता दें, प्रदेश के ग्रामीण और अंदरूनी क्षेत्रों के शिक्षक विहीन या एकल-शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. इसलिए 16,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का युक्तियुक्तकरण किया गया है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य की कुल 10463 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है.

संक्षिप्त समाचार

हैदराबाद के होटलों में मटन बताकर बीफ करते थे सप्लाई

हैदराबाद। हैदराबाद की क्राइम टीम, सेंट्रल क्राइम स्टेशन और फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम ने कई होटलों में मटन बताकर बीफ सप्लाई करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मल्लेपल्ली में उस्मान मीट शॉप के मालिक मोहम्मद उस्मान और अयान बीफ शॉप के कर्मचारी मोहम्मद जहांगीर पाशा के तौर पर हुई है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक, ये दोनों होटलों में मटन बताकर बीफ सप्लाई कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 50 किलो मीट जब्त किया गया, जिसमें बीफ मिला हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को हबीब नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

बम-बम भोले' के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू

श्रीनगर। पवित्र अमरनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ 'बम-बम भोले' के गगनभेदी जयकारों के बीच हो गया। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया। 57 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 3 जुलाई से पहलगाम और बालटाल, दोनों मार्गों से संचालित होगी और 28 अगस्त (रक्षाबंधन) को संपन्न होगी। पहले जत्थे में केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को शामिल किया गया, जिन्होंने पहले से पंजीकरण कराया था, ऋब्रड्ढ कार्ड प्राप्त किया था और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की थी। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक करीब चार लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा, परिवहन, आवास, संचार और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली हैं, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हो सके। यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को बेस कैंप का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं, ठहरने की व्यवस्था, बिजली-पानी की उपलब्धता, हेल्प डेस्क और अन्य इंतजामों का विस्तृत जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

तमिलनाडु में कम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता

कोयंबटूर। लंबे समय से बारिश न होने के कारण तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के वडमल्ली किसान अपनी फसल बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। थोंडामुथुर ब्लॉक में फूलों वाले पौधों के बड़े-बड़े हिस्से सूखने लगे हैं। इस इलाके के किसानों का कहना है कि गर्मियों में अच्छी बारिश न होने और उसके बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून की कम बारिश की वजह से पानी की भारी कमी हो गई है। इससे ओणम के मुनाफे वाले बाजार के लिए लगाई गई फसलों पर बुरा असर पड़ा है।

नारी शक्ति : वादों से लेकर कर दिखाने तक : ब्रिक्स में भारत का योगदान

रायपुर/मूक पत्रिका

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी-भारत ने 1 जनवरी 2026 को ÷लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण÷ की थीम के तहत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। महिलाओं से जुड़े मामलों में हमारा योगदान बेहद खास रहा है। हम सिर्फ़ कोई नारा या तारीफ़ के लिए सफल कहानियों का संग्रह पेश नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसा कामकाजी ढांचा लेकर आए हैं, जो करोड़ों महिलाओं तक पहुँचा है। यह ढांचा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां से शुरू होकर जहाँ भी जाता है, वहाँ आगे और विकसित होने के लिए तैयार रहता है।

यही भारत की खास बात है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से भारत ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर अपनाया है और इस काम को इतने बड़े पैमाने पर किया है, जिसकी बराबरी बेहद कम देश कर सकते हैं। 2023 में अपनी ब्र20 अध्यक्षता के दौरान, भारत ने वैश्विक सोच को ÷महिलाओं के विकास÷ से बदलकर ÷महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास÷ की ओर मोड़ने में मदद की। यह महज़ शब्दों का बदलाव नहीं था, बल्कि सोच का भी बदलाव था। महिलाओं को सिर्फ़ लाभार्थी के तौर पर देखने के बजाय, उन्हें नेतृत्वकारी भूमिका में देखना। कोच्चि में हम इसी बदलाव से जुड़ा सवाल उठा रहे हैं: एक बार वादा करने के बाद, उसे बड़े पैमाने पर, आख़िरी गाँव की आख़िरी महिला तक कैसे पहुँचाया जाए? भारत ने पिछले दस सालों में सिर्फ़ सैद्धांतिक तौर पर नहीं, बल्कि असल में इस सवाल का जवाब दिया है। भारत के लिए यह सोच नई नहीं, बल्कि बहुत पुरानी है। विकास की भाषा के आने से काफी पहले ही, हमारी संस्कृति ने नारी को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का स्रोत माना था। ये तीनों ही वे आधार हैं, जिन पर कोई भी समाज तरक्की करता है और उन्हें देवी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता रहा है। दैवीय शक्ति को ही 'शक्ति' कहा जाता है और संस्कृत के एक प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी प्रसन्न होते हैं। यह सम्मान सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं था: लोपामुद्रा और घोषा जैसी महिला ऋषियों ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की और गार्गी और मैत्रेयी जैसी दार्शनिकों ने उपनिषदों के प्रसिद्ध वाद विवादों में अपनी बात मज़बूती से रखी। इसलिए, भारत के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, किसी और से लिया हुआ विचार नहीं है, बल्कि एक प्राचीन विचार का ही आधुनिक रूप है। शुरुआत फ़ैसला लेने की प्रक्रिया से करते हैं। भारत की पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों में से लगभग आधी महिलाएँ हैं, जो दुनिया में चुनी हुई महिला नेताओं के सबसे बड़े समूहों में से एक है। इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का अंत सिर्फ़ प्रतिनिधित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां से इसकी शुरुआत होती है। ऐसा मॉडल, जो महिलाओं को सेवाएँ तो देता है, लेकिन उन सेवाओं को तय करने वाले फ़ैसलों में उन्हें शामिल नहीं करता, वह असल में महिलाओं के नेतृत्व वाला मॉडल नहीं है। भारत में सेवा पहुँचाने का ढाँचा तीन हिस्सों पर टिका है, जो एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। पहला हिस्सा है पहुँच: डिजिटल जन अवसंरचना, फ़ायदों को सीधे महिलाओं के हाथों तक पहुँचाती है। आधार से जुड़े ट्रांसफ़र उन बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर रहे हैं, जो पहले मदद पहुँचने से पहले ही उसे दूसरी तरफ़ मोड़ देते थे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इस पहुँच का व्यावहारिक उदाहरण है। 4.26 करोड़ से ज़्यादा माताओं को मातृत्व लाभ के तौर पर 20,060 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि सीधे उनके आधार से जुड़े खातों के ज़रिए मिली है। दूसरा हिस्सा है संस्थाएँ: डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, 10.05 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को 90.90 लाख से ज़्यादा स्वयं-सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जो दुनिया में महिलाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक संस्थाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तीसरा हिस्सा है गतिशीलता—यानी मूल्य श्रृंखला में हमेशा सबसे नीचे बने रहने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ने का एक सोच-समझकर चुना गया रास्ता। भारत अब 65,949 एसएचजी महिलाओं को बिज़नेस कॉरस्पोंडेंट एजेंट यानी बीसी सखी के तौर पर तैनात कर रहा है, जो दूर-दराज़ के इलाकों में जमा, क्रेडिट, धनराशि भेजने और पेंशन सेवाएँ पहुँचाती हैं। जो महिला कभी किसी लाभ के लिए कतार में लगती थी, अब वही महिला उस लाभ को दूसरों तक पहुँचाती है।

कुल मिलाकर ये सब मिलकर भागीदारी को आमदनी और मालिकाना हक में बदलते हैं। लखपति दीदी पहल के तहत, जून 2025 तक 1.48 करोड़ स्वयं सहायता समूह महिलाओं की सालाना कमाई कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुँच गई थी और जनवरी 2026 में शुरू किए गए उद्यमिता पर केंद्रित एक राष्ट्रीय अभियान का मकसद 50,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के ज़रिए 50 लाख अतिरिक्त महिलाओं को प्रशिक्षण देना है। तरक्की का यही रास्ता औपचारिक कारोबार में भी दिखता है: पीएमएमवाई के तहत दिए गए ऋण में से 69 प्रतिशत और 'स्टैंड-अप इंडिया' के लाभार्थियों में से 84 प्रतिशत महिलाएँ हैं। डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त 2.12 लाख स्टार्टअप्स में से 1.02 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक या हिस्सेदार है और इनमें से कई स्टार्टअप बड़े शहरों के बजाय छोटे शहरों में हैं। हम ब्रिक्स को ये ब्रांड नाम नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी पेश करते हैं: पहले पहुँच, फिर संस्थाएँ और फिर लाभार्थी से उद्यमी बनने का एक व्यवस्थित मार्ग।

आँकड़े भी इस बदलाव को दिखाते हैं। भारत में महिलाओं की कामकाजी आबादी में भागीदारी 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है और इसी दौरान महिलाओं में बेरोज़गारी दर 5.6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई है। अब पहले से कहीं ज़्यादा महिलाएँ कार्यबल का हिस्सा हैं, इसलिए हमारा फ़ोकस अब अगले चरण पर है, उनके काम की गुणवत्ता और आमदनी को और बेहतर बनाना। इस साल महिलाओं से जुड़े कामों के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र तय किए गए हैं और इनमें से एक सीधे हमारे अनुभव से जुड़ा है: जलवायु कार्यवाही, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका। इस बारे में साक्ष्य भी साफ नतीजे बयां करते हैं: जब फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाएं शामिल होती हैं, तो पोषण बेहतर मिलता है और समुदाय चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। झारखंड में महिला किसानों को ऐसी बीजों की किस्मों की जानकारी है, जो सूखे के दौरान भी बची रहती हैं। राजस्थान में महिला पशुपालकों को उन रास्तों की भी जानकारी है, जिनसे सूखे के समय मवेशियों को सुरक्षित ले जाया जा सकता है। भारत का काम ऐसे संस्थान बनाना रहा है, जो इस जानकारी और अनुभव का इस्तेमाल करें, न कि इसे नज़रअंदाज़ करें। मिशन पोषण 2.0 आंगनवाड़ी नेटवर्क के ज़रिए चलाया जाता है, जिसमें महिलाएं काम करती हैं और वे ही लोगों तक सेवा पहुंचाने की भरोसेमंद कड़ी होती हैं। जलवायु के अनुसार ढलने का काम भी इसी तरह होता है, चाहे वह लद्दाख में महिलाओं द्वारा बनाए गए ऊंचे इलाकों में पानी जमा करने के ढांचे हों या ओडिशा के तट पर वनस्पति के घने इलाकों को बचाने वाली समितियां। महिलाएं अब सिर्फ़ अनुकूलन की तकनीक का इस्तेमाल करने वाली नहीं रह गई हैं, बल्कि वे खुद इसे आगे बढ़ा भी रही हैं: नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को खेती में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह ज़्यादा कौशल और ज़्यादा आमदनी वाले काम की ओर एक सोच-समझकर उठाया गया कदम है।

कोर्ट के आदेश पर सरपंच, सचिव और कब्जाधारी के खिलाफ़ FIR दर्ज

रायगढ/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत के द्वारा गरीबी उन्मूलन के तहत प्राप्त हितग्राही की दुकान को अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त दुकान उसे आबटित होने का दावा करते हुए जबरन कब्जा कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं जनपद पंचायत सीईओ द्वारा मूल हितग्राही को दुकान का कब्जा दिलवाने पंचायत को आदेश दिये जाने के बाद भी न तो पंचायत ने कोई कार्रवाई की और न ही कब्जेधारी ने कब्जा खाली किया। इस बात से परेशान हो कर ग्रामीण ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। वहीं न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व अवैध कब्जाधारी के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घरघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कुडुमकेला निवासी रविशंकर श्रीवास ने घरघोड़ा न्यायालय में परिवाद दायर करते हुए बताया था कि ग्राम पंचायत कुडुमकेला के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन के तहत नाई एवं धोबी की दुकान का निर्माण कराया गया है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्डधारी को आबंटित किया जाना था। उक्त दुकान निर्माण के बाद ग्राम पंचायत कुडुमकेला के सरपंच, उपसरपंच एवं पंचगण द्वारा 20 अप्रैल 2009 को एक सहमति पत्र निष्पादित किया गया जिसमें उपरोक्त निर्मित दुकान में से नाई की दुकान को पात्रता के आधार पर उसे खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीं रविशंकर श्रीवास ग्राम पंचायत की सहमति से उक्त दुकान को खोलने की तैयारी करने लगा इसी बीच गांव का ही एक अन्य नाई सुंदर लाल श्रीवास ने रविशंकर के साथ विवाद करते हुए ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उक्त दुकान को उसे आबंटित किया जाना कहते हुए अपना कब्जा जमाते हुए दुकान खोल लिया गया। चूंकि रवि शंकर को पूर्व से ग्राम पंचायत का सहमति प्राप्त थी लिहाजा उसने 16 नवंबर 2009 को घरघोड़ा एसडीएम के समक्ष कब्जा दिलवाने का निवेदन किया गया था जिस पर एसडीएम ने नियमानुसार कार्यवाही करने जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया था।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में चिरायु टीम ने किया स्वास्थ्य परीक्षण

100 बालिकाओं की हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप व सिकल सेल जांच, सैनिटरी पैड वितरित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

स्वास्थ्य विभाग जिला बेमेतरा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोहलेडर के निर्देश एवं बी.एम.ओ. खंडसरा डॉ. शरद कोहाड़े के मार्गदर्शन पर बीते गुरुवार को शासकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बेमेतरा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत चिरायु टीम 'सी' खंडसरा द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यालय में निवासरत सभी 100 बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान सभी बालिकाओं की हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप एवं सिकल सेल की जांच की गई। सामान्य बीमारियों से पीड़ित पाई गई बालिकाओं को मौके पर ही आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विद्यालय में निवासरत समस्त किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया। टीम ने माहवारी स्वच्छता प्रबंधन एवं व्यक्तिगत साफ-सफाई के संबंध में बालिकाओं को जानकारी दी। इस अवसर पर चिरायु टीम से डॉ. दिलीप चंद्रवंशी, डॉ. प्रीति ठाकुर, फार्मासिस्ट बलवंत बंजारे, लैब टेक्नीशियन मनीष साहू उपस्थित थे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की अधीक्षिका श्रीमती भारती घृतलहरे सहित विद्यालय के अन्य स्टाफ ने सहयोग प्रदान किया।राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बीमारियों का शीघ्र पहचान, उपचार एवं रेफरल कर बच्चों को स्वस्थ बनाना है।

'डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम' से खेत से लेकर सोशल मीडिया तक सशक्त होगा किसान : दक्ष वैद्य साहू

किसान मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता को डिजिटल योद्धा बनाने का संकल्प, सरल ऐप से होगा प्रशिक्षण

रायपुर/मूक पत्रिका

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सोशल मीडिया प्रदेश सहप्रभारी दक्ष वैद्य साहू ने कहा कि भाजपा का डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' एवं 'तकनीक-संपन्न किसान' के विजन को धरातल पर उतारने वाला एक दूरदर्शी अभियान है। यह कार्यक्रम किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाकर गांव-गांव तक पार्टी की रीति-नीति और सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। श्री साहू ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर के नेतृत्व में किसान कल्याण को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने का जो संकल्प लिया गया है, उसी तर्ज पर किसान मोर्चा भी अपने प्रत्येक पदाधिकारी एवं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को डिजिटल प्रशिक्षण से जोड़ेगा। हमारा लक्ष्य है कि खेत में हल चलाने वाला किसान और सोशल मीडिया पर विचार रखने वाला कार्यकर्ता, दोनों एक साथ डिजिटल रूप से सशक्त हों। क्यों जरूरी है किसान मोर्चा का डिजिटल होना? श्री दक्ष वैद्य साहू ने कहा कि आज एमएसपी, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, ड्रोन तकनीक और प्राकृतिक खेती जैसी दर्जनों योजनाएं केंद्र व राज्य सरकार चला रही है। लेकिन जब तक ये जानकारियां समय पर किसान तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। डिजिटल प्रशिक्षण से किसान मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता 'डिजिटल प्रचारक' बनकर इन योजनाओं को मोबाइल के माध्यम से हर खेत-खलिहान तक पहुंचाएगा। साथ ही विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का भी तथ्यों के साथ त्वरित खंडन कर सकेगा। सरल ऐप पर चार मॉड्यूल में प्रशिक्षण दक्ष वैद्य साहू ने बताया कि भाजपा के आधिकारिक 'सरल ऐप' पर यह प्रशिक्षण चार मुख्य मॉड्यूल में दिया जाएगा: 1. भाजपा की किसान-हितैषी विचारधारा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से नरेंद्र मोदी तक का इतिहास 2. संगठन, नेतृत्व और पंचनिष्ठा के मूल सिद्धांत 3. नमो ऐप के माध्यम से जनसंपर्क व फीडबैक की तकनीक 4. पीएम किसान, श्रीअन्न योजना, कृषि इंफ्रा फंड सहित छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना जैसी योजनाओं का डिजिटल प्रसार वीडियो लेक्चर, ई-बुक और लाइव सेशन के जरिए प्रशिक्षण के बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी। उत्तीर्ण कार्यकर्ताओं को पार्टी द्वारा डिजिटल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

हर मंडल में बनेगी 'डिजिटल किसान सेना' -श्री साहू ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी जी के आह्वान पर किसान मोर्चा ने भी संभाग, जिला व मंडल स्तर पर सोशल मीडिया प्रभारियों की टीम सक्रिय कर दी है। हम 'हर बूथ-दस यूथ, हर मंडल-डिजिटल मंडल' के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। बूथ स्तर पर तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को जोड़कर 'डिजिटल किसान सेना' तैयार की जाएगी जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसान की आवाज बनेगी। दक्ष वैद्य साहू ने कहा कि जब किसान का बेटा डिजिटल होगा, तभी गांव का भविष्य डिजिटल बनेगा। यह प्रशिक्षण अभियान 2026 के नगरीय निकाय चुनाव और आगामी सभी चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक विजय की आधारशिला रखेगा।

भाजपा का 'डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम' महिला शक्ति को डिजिटल युग में सशक्त बनाने की क्रांतिकारी पहल : रत्नावली कौशल

बूथ सखियों तक डिजिटल प्रशिक्षण पहुंचाने का लक्ष्य, महिला मोर्चा कर रहा घर-घर संपर्क

रायपुर/मूक पत्रिका

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं छत्तीसगढ़ शासन के अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की पूर्व सदस्य रत्नावली कौशल ने कहा कि भाजपा द्वारा प्रारंभ किया गया डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'डिजिटल इंडिया' के विजन को साकार करने वाला और महिला कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने वाला एक ऐतिहासिक अभियान है। रत्नावली कौशल ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी के मार्गदर्शन में इस विशेष प्रशिक्षण अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने की संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक 'बूथ सखी' डिजिटल रूप से प्रशिक्षित होकर पार्टी की विचारधारा, इतिहास, नेतृत्व की पंचनिष्ठा और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाए। रत्नावली कौशल ने कहा कि आज का युग सूचना का युग है। त्वरित जानकारियां, राष्ट्रीय मुद्दे और जनहित के विषय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आमजन तक पहुंचते हैं। ऐसे में भाजपा महिला मोर्चा की प्रत्येक कार्यकर्ता का डिजिटल क्षेत्र में दक्ष होना समय की मांग है। इससे न केवल संगठन मजबूत होगा, बल्कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगा। रत्नावली कौशल ने बताया कि यह प्रशिक्षण भाजपा के आधिकारिक 'सरल ऐप' के माध्यम से पूर्णतः डिजिटल रूप से दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के चार प्रमुख मॉड्यूल हैं:1. भाजपा की विचारधारा और गौरवशाली इतिहास

2. नेतृत्व, संगठन संरचना और पंचनिष्ठा के सिद्धांत 3. नमो ऐप का प्रभावी उपयोग 4. केंद्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार की जन-कल्याणकारी विकास योजनाओं का डिजिटल प्रचार-प्रसार प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को मोबाइल ऐप पर वीडियो लेक्चर एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आधारित परीक्षा ली जाएगी और सफल कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। बूथ सखी तक पहुंचेगा अभियान -रत्नावली कौशल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी जी के निर्देशानुसार संभाग, जिला एवं विधानसभा स्तर पर महिला प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। राज्य और मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर बूथ स्तर की कार्यकर्ताओं, मंडल प्रभारियों और पदाधिकारियों को जोड़ा जा रहा है। महिला मोर्चा की टीम स्वयं बूथ सखियों के बीच जाकर उन्हें डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करेगी। रत्नावली कौशल ने बताया कि यह अभियान न केवल महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा, बल्कि 2026 के नगरीय निकाय एवं आगामी चुनावों में भाजपा की विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा।

डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जांता, बेमेतरा में करियर मार्गदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

बेमेतरा जिले के एकमात्र डीएवी विद्यालय एवं दाढ़ी क्षेत्र के एकमात्र सीबीएसई स्कूल, डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, जांता में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं एवं करियर निर्माण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष करियर मार्गदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को नीट एवं जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, अध्ययन तकनीक, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण तथा मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं प्रमुख वक्ता मेमोरी गुरु, शिक्षाविद्, समाधान कॉलेज के डायरेक्टर एवं शिक्षा अकादमी के संस्थापक अवधेश पटेल सर ने विद्यार्थियों को सफलता के मूल मंत्र से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में विद्यार्थियों को नीट और जेईई की तैयारी के लिए बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सही मार्गदर्शन, अनुशासित अध्ययन और प्रभावी रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।अवधेश पटेल सर ने विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति विकास, अध्ययन कौशल, समय प्रबंधन, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास बढ़ाने के व्यावहारिक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि निरंतर अभ्यास, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। उनके प्रेरणादायक उद्बोधन ने विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। इस अवसर पर जेईई परीक्षा में 99.9 पर्सेंटाइल प्राप्त कर आईआईटी गुवाहाटी में 2011 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने वाले छात्र रूपेश वर्मा जो कि आई सी आई सी आई बैंक मुंबई में चीफ़ मैनेजर के पद पर कार्य किये है, 11 साल कॉर्पोरेट जगत और इसी दौरान पार्ट टाइम नीट और जे ई ई के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव भी आईआईटीयन रुपेश वर्मा जी को है, आपके मार्गदर्शन से बहुत से विद्यार्थियों का नीट और जे ई ई में चयन हुआ है। आपने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने अपनी सफलता की यात्रा, नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। विद्यार्थियों ने उनके अनुभवों को अत्यंत प्रेरणादायक एवं उपयोगी बताया।विद्यालय के प्राचार्य पी. एल. जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में विद्यार्थियों को सही दिशा, उचित मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अनुशासन, आत्मविश्वास और मेहनत ही सफलता की कुंजी है तथा ऐसे मार्गदर्शन कार्यक्रम विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं।

प्राचार्य श्री जायसवाल ने विद्यार्थियों को अपने समय का सदुपयोग करने, सकारात्मक सोच बनाए रखने तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इस प्रकार के जागरूकता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आगे भी समय-समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि विद्यार्थियों को अपने भविष्य के निर्माण के लिए सही दिशा और आवश्यक जानकारी प्राप्त होती रहे।कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने इसे अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा व्यक्त की तथा मुख्य वक्ता अवधेश पटेल जी और रुपेश वर्मा जी के मार्गदर्शन को अपने करियर निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

परसदा छोटे में संदिग्ध मौत से हड़कंप, अवैध शराब के कारोबार पर उठे बड़े सवाल

बरमकेला/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत परसदा छोटे में गुरुवार को हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। गांव के निवासी जलसाय बरिहा का शव सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद गांव में शोक के साथ-साथ आक्रोश का माहौल है। घटना के बाद ग्रामीणों ने गांव में वर्षों से चल रहे अवैध महुआ शराब के कारोबार को इस मौत की बड़ी वजह बताते हुए पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जानकारी के अनुसार, जलसाय बरिहा बुधवार रात करीब 8 बजे घर से निकला था। देर रात तक उसके वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन लगातार बारिश और अंधेरे के कारण उसका कोई पता नहीं चल सका। गुरुवार शाम करीब 4 बजे कुछ ग्रामीणों ने सड़क किनारे बने गड्ढे में एक शव देखा। पास जाकर देखने पर उसकी पहचान जलसाय बरिहा के रूप में हुई। सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही कनकबीरा चौकी प्रभारी टीकाराम खटकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में

लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को ग्रामीणों से यह जानकारी मिली है कि मृतक शराब के नशे में था तथा तेज बारिश के दौरान अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गया होगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

घर-घर बिक रही अवैध महुआ शराब, ग्रामीणों में भारी नाराजगी-इस घटना के बाद गांव में सबसे बड़ा मुद्दा अवैध महुआ शराब का कारोबार बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि परसदा छोटे में लंबे समय से खुलेआम अवैध महुआ शराब की बिक्री हो रही है। गांव के कई घरों में दिन-रात शराब बेची जाती है, लेकिन इस पर प्रभावी रोक लगाने में पुलिस और संबंधित विभाग पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि शराब खरीदने के लिए किसी ठेके तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहल्लों और घरों में आसानी से महुआ शराब उपलब्ध हो जाती है।

इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। कई घरों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, घरेलू विवाद बढ़े हैं और नशे की वजह से लोगों की जान तक जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार पुलिस, आबकारी विभाग और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई केवल औपचारिक बनकर रह गई। कुछ दिनों तक सख्ती दिखाई जाती है, फिर अवैध कारोबार पहले की तरह शुरू हो जाता है। लोगों का कहना है कि यदि लगातार और प्रभावी कार्रवाई होती, तो गांव में इस तरह खुलेआम अवैध शराब का कारोबार नहीं चलता।

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल-जलसाय बरिहा की मौत के बाद ग्रामीणों में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि जब गांव में लंबे समय से अवैध शराब बिक रही थी, तब संबंधित विभागों ने इसे पूरी तरह बंद कराने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। लोगों का कहना है कि समय-समय पर शिकायतें करने के बावजूद यदि अवैध शराब का कारोबार लगातार जारी रहा, तो यह प्रशासनिक नियंत्रण की कमजोरी को दर्शाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि गांव में अवैध शराब की उपलब्धता पर प्रभावी नियंत्रण होता, तो संभव है कि आज एक परिवार अपना सदस्य न खोता।

> गांव में बिक रही अवैध शराब की शिकायत कई बार की गई है परंतु अब तक कार्यवाही में कमी देखी जा यही है
>
> **कौशल्या सत्येंद्र सिदार**
> **सरपंच ग्राम पंचायत परसदा छोटे**

मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई नहीं होने की बात सही नहीं है। पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है और आगे भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

टीकाराम खटकर, चौकी प्रभारी, कनकबीरा

पत्थलगांव में प्रशासन की 'कुंभकर्णी नींद': वार्ड क्रमांक 14 में अधूरी सीसी रोड बनी मुसीबत, क्या CM हेल्पलाइन 1076 जगा पाएगी सिस्टम को?

पत्थलगांव/मूक पत्रिका

विकास के दावों की हवा निकालती एक बेहद शर्मनाक तस्वीर पत्थलगांव के वार्ड क्रमांक 14 (लोकमान्य तिलक वार्ड) से सामने आ रही है। यहाँ का मुख्य सीसी रोड पिछले लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि कई बार लिखित और मौखिक शिकायतों के बाद भी अफ़सरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। अब हार मानकर त्रस्त नागरिकों ने सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर गुहार लगाई है।

बरसात आते ही बन जाते हैं 'बाढ़' जैसे हालात-मौसम विभाग ने मानसून की दस्तक दे दी है, और इसी के साथ वार्ड नंबर 14 के बाशिंदों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अधूरी सड़क के कारण यहाँ निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।

कमर तक भर जाता है पानीः पहली ही बारिश में पूरी सड़क समंदर में तब्दील हो जाती है। सड़क पर

कमर तक पानी भरना यहाँ आम बात हो चुकी है।घरों में घुस रहा गंदा पानीः यह दूषित और कीचड़युक्त पानी लोगों के ड्राइंग रूम और किचन तक में प्रवेश कर जाता है, जिससे लाखों का नुकसान और संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है।ठप जनजीवनः स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों का इस नरकीय स्थिति में घर से निकलना भी दूभर हो गया है।

÷शिकायतों की रद्दी तो बहुत बनी, अब देखना है कि 1076 पर कोई एक्शन होता है या यह मामला भी पुरानी फाइलों की तरह दबा दिया जाएगा।÷

वार्ड के आक्रोशित नागरिक बड़ा सवालः जनता के टैक्स का पैसा कहाँ गया?

ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की साठगांठ का खामियाजा यहाँ की आम जनता भुगत रही है। सड़क निर्माण का काम आधा क्यों छोड़ा गया? जब बजट पास हुआ था, तो काम को अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचाया गया? इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है।

अब 'कमांड सेंटर' पर टिकी हैं निगाहें!

स्थानीय प्रशासन के निकम्मेपन से तंग आकर अब सीधे सूबे के मुखिया की हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाया गया है। वार्डवासियों का साफकहना है कि यह उनकी आखिरी उम्मीद है।अब देखना यह होगा कि ष्टरू हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज इस शिकायत के बाद सोए हुए अफ़सर जागते हैं और ठेकेदार पर हंटर चलता है, या फिर इस बार भी पत्थलगांव की जनता को इस नारकीय दलदल में डूबने के लिए लावारिस छोड़ दिया

डीएमएफसे 13 विकास कार्यों के लिए 35.77 करोड़ की मिली प्रशासकीय स्वीकृति, खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास, कृषि एवं ग्रामीण अधोसंरचना को मिलेगा नया आधार

मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री के विशेष प्रयासों से जिले के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे लगातार प्रयास

रायगढ़/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तथा वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी के विशेष प्रयासों से जिले के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे है। इसी क्रम में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 35 करोड़ 76 लाख 94 हजार रुपये की लागत के 13

महत्वपूर्ण विकास कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से धरमजयगढ़, लैलूंगा, घरघोड़ा एवं तमनार विकासखंडों में शिक्षा, कौशल विकास, कृषि अधोसंरचना तथा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को नई मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ निधि का उपयोग ऐसे विकास कार्यों में किया जा रहा है, जिनका खनन प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों एवं ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। स्वीकृत परियोजनाएं क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी नई गति देंगी।

तमनार, घरघोड़ा, लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ में पुस्तकालय भवन निर्माण की स्वीकृति-ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तमनार, घरघोड़ा, लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ विकासखंडों में पुस्तकालय भवन निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ 39 लाख 64 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पुस्तकालयों में आधुनिक अध्ययन संसाधन विकसित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का वातावरण उपलब्ध होगा।

जिला जेल का कलेक्टर एवं एसएसपी ने किया आकस्मिक निरीक्षण, जेल में सुरक्षा व्यवस्था एवं बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की ली जानकारी

जेल परिसर में अवैध गतिविधियों, मारपीट और प्रतिबंधित सामग्री पर जीरो टॉलरेंस के निर्देश

रायगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह ने शुक्रवार को जिला जेल रायगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल में सुरक्षा व्यवस्था एवं बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर गोकुल आर.के., एडीएम अपूर्व प्रियेश टोप्पो, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं एसएसपी ने बंदी बैरकों, जेल अस्पताल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, प्रिजन कॉलिंग सुविधा, बंदी मुलाकात कक्ष तथा

पाकशाला का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन एवं बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं प्रत्येक बंदी तक समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पहुंचनी चाहिए। जिला जेल को सुरक्षित, अनुशासित, पारदर्शी और सुधारोन्मुख संस्था के रूप में संचालित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर एवं एसएसपी ने जेल में निरुद्ध बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और सुझावों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित, संवेदनशील एवं नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि बंदियों के अधिकारों और गरिमा का पूर्ण संरक्षण हो सके। निरीक्षण के दौरान बंदी मुलाकात कक्ष में उपस्थित परिजनों से भी अधिकारियों ने चर्चा की। उन्होंने परिजनों से कहा कि यदि किसी भी स्तर पर मारपीट, अवैध धन वसूली अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिले तो उसकी तत्काल शिकायत करें, ताकि दोषियों के विरुद्ध बिना विलंब कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने जेल परिसर तक प्रतिबंधित एवं अवैध सामग्री पहुंचने की संभावित कमजोर कड़ियों की पहचान कर उन्हें तत्काल समाप्त करने तथा निगरानी एवं सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक श्री गोवर्धन सिंह सोरी ने जेल में उपलब्ध व्यवस्थाओं, सुधारात्मक एवं पुनर्वास गतिविधियों तथा बंदियों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।

मल्का पावर परियोजना विवाद पहुंचा कानूनी दहलीज तक, शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर!

धरमजयगढ़/मूक पत्रिका

बहुप्रतीक्षित मल्का जल विद्युत परियोजना से जुड़ा विवाद अब नए चरण में प्रवेश कर गया है। परियोजना संचालन से संबंधित शिकायतों और आरोप-प्रत्यारोप के बीच थाना धरमजयगढ़ पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद एक व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 एवं 115 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार, धनवाड़ा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से थाना धरमजयगढ़ में एक विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में कंपनी प्रबंधन ने आरोप लगाया था कि परियोजना से पूर्व में जुड़े रहे एक व्यक्ति द्वारा कंपनी की गतिविधियों को प्रभावित करने, अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दबाव बनाने तथा परियोजना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है।और वहीं पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने के बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए तथ्यों और दस्तावेजों की जांच की। जांच प्रक्रिया के दौरान संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए। वहीं

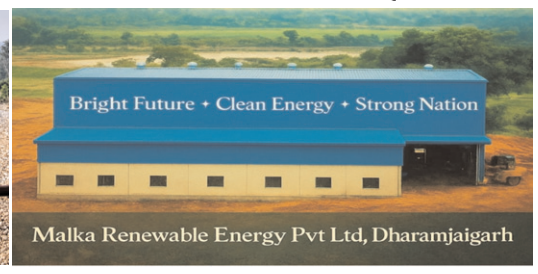

प्रारंभिक जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।प्राप्त जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में कंपनी के एजीएम विवेक सिंह ने उल्लेख किया है कि रोहित राज श्रीवास्तव पूर्व में कंपनी से जुड़े लाइजनिंग कार्यों का दायित्व संभालते थे। कंपनी का दावा है कि वर्ष 2025 में उनकी कार्यशैली एवं व्यवहार से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते उन्हें कार्य से पृथक कर दिया गया था। इसके बाद से संबंधित व्यक्ति द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से आरटीआई आवेदन लगाकर कंपनी और कई शासकीय विभागों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को कथित रूप से मानसिक दबाव में रखा जा रहा था तथा ग्रामीणों को भड़काकर विरोध का माहौल निर्मित करने की कोशिश की जा रही थी। कंपनी का दावा है कि यदि ऐसी गतिविधियां जारी रहती हैं तो परियोजना के संचालन और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका है।इधर, एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले ने और अधिक गंभीर रूप ले लिया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि विवेचना अभी जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, मल्का पावर परियोजना से जुड़ा यह विवाद क्षेत्र का प्रमुख चर्चा विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें पुलिस एफआईआर के बाद आगामी कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं, जिससे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक संपन

सारंगढ़/मूक पत्रिका

ग्रामीण विकास की गति को तेज करने और खरीफ फसलों के लिए किसानों को खाद, बीज, कीट नाशक दवा उचित समय पर मिले और त्वरित निराकरणहो के उद्देश्य से जिपं अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आयोजित हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यकार्य पालन अधिकारी इंद्रजीत बर्मन, विभिन्न विभागों के जिला स्तर के अधिकारी तथा जिपं सदस्य गण उपस्थित रहे बैठक के दौरान जिले में चल रही विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति का विस्तृत समीक्षा की गई। जिपं अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय ने कहा कि - धरातल पर योजनाओं का लाभ तब तक आमजनों को नहीं मिल सकता, जब तक विभागों के बीच आपसी समन्वय, तालमेल मजबूत न हो। जिपं अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि - सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। जनहित के किसी भी कार्यों को तकनीकी कारणों या अन्य छोटी मोटी कारणों से नहीं अटकाया जाए । ग्रामीण विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक

विकास की किरणें पहुंचे, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।इस में किसी भी प्रकार कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।

बैठक में उपस्थित जिपं सदस्यों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विभिन्न विकास योजनाओं, कार्यों समस्याओं को प्रमुखता से उठाए।जिपं अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि - सदस्यों के द्वारा उठाए गए सभी जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए और एक निश्चित समय सीमा के भीतर उन मांगो,समस्याओं के समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन, सड़क पुल पुलिया खाद, बीज, कीट नाशक दवा, बिजली पानी , मौसमी बीमारी के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाई की उपलब्धता पर बैठक में विस्तृत समीक्षा किया गया। जिपं अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि - सभी अधिकारी गांव गांव में जाएं और लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि - विभागों के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी स्वयं करें। निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्ता पूर्ण हो ये बात सुनिश्चित करें। कृषि, उद्यानिकी, खाद्य सहकारिता , सड़क, जल संसाधन आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा किया गया। आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में जिपंअध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय, उपा अजय नायक, सांसद प्रतिनिधि, जिपंसदस्य गण डॉ दिनेश,श्रीमती शिव कुमारी साहू , श्रीमती भगवंती पटेल, सुशीला साहू, श्रीमती लता लक्ष्में, श्रीमती डॉ अभिलाषा नायक, श्रीमती सहोदरा सिदार विनोद भारद्वाज सीईओ इंद्रजीत बर्मन एवम अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कलेक्टर के निर्देश पर सारंगढ़ क्षेत्र के विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण, बिना सूचना अनुपस्थित शिक्षक को नोटिस

बरमकेला/मूक पत्रिका

जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, विद्यालयों में अनुशासन एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देशानुसार शासकीय विद्यालयों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़ श्रीमती सोमा सिंह ठाकुर ने सारंगढ़ विकासखंड के विभिन्न शासकीय विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने शासकीय प्राथमिक शाला मौहापाली, शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला छोटे खैरा तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदी का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति, कक्षा संचालन, पाठ्यक्रम की प्रगति, शिक्षण की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, मध्यान्ह

भोजन, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। साथ ही विद्यालयों के उपस्थिति पंजी, शैक्षणिक अभिलेखों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया।निरीक्षण के दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे, इसके लिए नियमित कक्षा संचालन, गतिविधि आधारित शिक्षण एवं सतत मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जाए, जिससे विद्यार्थियों में सीखने की रुचि बढ़े और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उनके लिए विशेष शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने तथा नियमित अभ्यास कराने पर भी बल दिया गया।

इस अवसर पर संकुल प्राचार्य श्रीमती विभावरी सिंह ठाकुर एवं विकासखंड श्रोत समन्वयक सत्येंद्र बसंत भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन करते हुए शिक्षकों को शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध अध्यापन तथा विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने विभिन्न कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया तथा उनसे विषयवार प्रश्न पूछकर उनके सीखने के स्तर का आकलन किया। विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन, समय का सदुपयोग तथा लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास एवं आत्मविश्वास के साथ अध्ययन करने से बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदी में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ विशेष चर्चा कर उन्हें समय प्रबंधन, नियमित पुनरावृत्ति, मॉडल प्रश्नपत्रों के अभ्यास तथा सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी गई। विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से दूर रहकर आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी जारी रखने के लिए भी प्रेरित किया गया। निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला छोटे खैरा में पदस्थ शिक्षक श्री कुमारमणि हरिप्रिया बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उनके विरुद्ध तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रचलित सेवा नियमों के तहत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में स्वच्छता, अनुशासन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

÷कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार विद्यालयों का नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। सभी शिक्षकों को पूरी जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना सूचना अनुपस्थित रहने अथवा कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।÷

सोमा सिंह ठाकुर
विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़

संपादकीय

नई ईवी नीति- इलेक्ट्रिक वाहनों से घटेगा प्रदूषण या बढ़ेंगी आम लोगों की मुश्किलें?

दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की बदहाली छिपी नहीं है। इसे बेहतर बनाने के लिए किसी भी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए हैं, ताकि लोग निजी वाहनों के बारे में न सोचें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति के जरिए अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने में मदद मिलती है, तो इसे एक बेहतर उपाय माना जाएगा। इसमें कोई दोराय नहीं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के मद्देनजर इसकी मुख्य वजहों की पहचान और उनसे निपटने के लिए ठोस उपाय करना जरूरी है। मगर इस क्रम में सरकार जिन नीतियों का सहारा लेना चाहती है, वे व्यापक जनहित में हों, यह सुनिश्चित किया जाना भी वक्त का तकाजा है।देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण एक अहम समस्या के रूप में चिंता का मुद्दा बना रहता है। इसके लिए सड़क पर चलने वाले वाहनों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। खासतौर पर दुपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या न केवल सुव्यवस्थित यातायात, बल्कि प्रदूषण के लिहाज से अपेक्षया ज्यादा बहस के केंद्र में रहती है।इन्हीं बिंदुओं के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अगले वर्ष जनवरी से सिर्फ ई-ऑटो यानी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। साथ ही, जनवरी 2028 से सिर्फ ई-दुपहिया वाहनों का ही पंजीकरण कराया जा सकेगा। नई नीति के तहत अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सड़क-कर और पंजीकरण शुल्क में छूट की व्यवस्था भी की गई है।जाहिर है, सरकार ने एक तरह से नीतिगत तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के क्रम में एक ठोस फैसला किया है, लेकिन चूंकि इसका वैसे लोगों के जीवन पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है, जिनकी रोजी-रोटी इन वाहनों से जुड़ी होती है, इसलिए फिलहाल इसके कई अन्य पहलुओं पर बहस जारी है।हालांकि यह भी एक तथ्य है कि दिल्ली में पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदूषण की वजह से हालात बेहद चिंताजनक होते गए हैं, तो इसमें वाहनों की खासी भूमिका रही है। मगर इसमें कारों और अन्य वाहनों के बरक्स दुपहिया और तिपहिया वाहनों की कितनी भूमिका है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। खासतौर पर इसलिए भी कि दिल्ली में तिपहिया वाहन आमतौर पर सीएनजी से चलते हैं। एक समय पेट्रोल और डीजल वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण व्यापक चिंता का विषय बना था और उस समय सीएनजी वाहनों के जरिए दिल्ली की हवा को स्वच्छ करने के दावे किए गए थे। लेकिन आज भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। वहीं, इलेक्ट्रिक कचरा आज विश्वभर में पर्यावरण के सामने एक नई चुनौती बन रहा है।यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस नीति के केंद्र में फिलहाल जिन दुपहिया और तिपहिया वाहनों को रखा गया है, वे बड़ी संख्या में साधारण लोगों की आजीविका और आवागमन का मुख्य सहारा रहे हैं। नई नीति की अनिवार्यता की स्थिति में अपने वाहन को इलेक्ट्रिक प्रणाली में बदलना कम आयवर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकता है।दूसरी ओर, दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की बदहाली छिपी नहीं है।

देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि जो हाथ उनके पानी को छुएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिए।

पानी पाकिस्तान का बंद हुआ है, मगर गला यहां के 'शांति दूतों' का क्यों सूख रहा है?

(नीरज कुमार दुबे)

देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखानी शुरू की है, उससे इस्लामाबाद की सत्ता, सेना और वहां के कथित लोकतांत्रिक चेहरे बुरी तरह बौखला गए हैं। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले ने पाकिस्तान की नसों में ऐसा डर भर दिया है कि वहां के नेता लगातार धमकियां दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रो रहे हैं और दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने उनके अस्तित्व पर हमला कर दिया है।

देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि जो हाथ उनके पानी को छुएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिए। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने दुनिया को डराने की कोशिश की कि यदि सिंधु जल संधि नहीं बची तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की पूरी विश्व व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी।

लेकिन पाकिस्तान के इन आंसुओं के पीछे छिपा सच पूरी दुनिया जानती है। पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां से आए थे? जम्मू-कश्मीर में दशकों से आतंकवाद को कौन पालता रहा है? भारत के सैनिकों और नागरिकों का खून बहाने के लिए हथियार, प्रशिक्षण और धन कौन देता रहा है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके यह स्पष्ट कर दिया कि अब नई दिल्ली पुरानी नीति पर नहीं चलेगी। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाए रखेगा तो उसे हर मोर्चे पर कीमत चुकानी होगी। भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकार वाले जल के उपयोग को तेज करने का फैसला किया है। यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों का प्रयोग है।

साथ ही सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो भारत में बैठकर पाकिस्तान से वार्ता की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक सौ से अधिक तथाकथित बुद्धिजीवियों, नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत बहाल करने, वीजा सेवाएं शुरू करने, दूतावास सामान्य करने और यहां तक कि कश्मीर पर फिर से बातचीत करने की मांग की है। इस पत्र पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक और कुछ अन्य भारतीय हस्तियों के हस्ताक्षर भी हैं।

इन लोगों से देश पूछना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? जो देश भारत में आतंकवादी भेजता है, हमारे नागरिकों की हत्या करवाता है, सीमा पार से गोलियां चलाता है, उसी देश के लिए इनके दिल में इतनी बेचैनी क्यों उमड़ती है? भारत ने जब पाकिस्तान का पानी रोकने की दिशा में कदम उठाया तो प्यास पाकिस्तान को लगी, लेकिन गला यहां बैठे तथाकथित शांति दूतों का सूखने लगा। आखिर क्यों? क्या इन लोगों को भारत की सुरक्षा से ज्यादा चिंता पाकिस्तान की खेती और उसकी बिजली व्यवस्था की है?

ये लोग कहते हैं कि वार्ता ही समाधान है। लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं? लाहौर बस यात्रा से लेकर आगरा शिखर वार्ता तक और उफा से लेकर शरम अल शेख तक भारत ने हर बार शांति का हाथ बढ़ाया। बदले में मिला क्या? कारगिल, संसद हमला, मुंबई हमला, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम। पाकिस्तान हर बार वार्ता की मेज पर मुस्कुराता है और पीठ पीछे आतंकियों को भेजता है।

आज जब भारत पहली बार कठोर नीति पर डटा है तो देश के भीतर बैठे कुछ लोग बेचैन हो उठे हैं। उन्हें आतंकवाद पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का पानी रुकने पर दर्द होने लगता है। उन्हें भारत के शहीदों की चिंता कम और इस्लामाबाद की परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। यह वही मानसिकता है जिसने दशकों तक भारत को कमजोर नीति में बांध कर रखा।

सच यह है कि सिंधु जल संधि का सबसे ज्यादा लाभ पाकिस्तान ने उठाया। भारत ने वर्षों तक उदारता दिखाई, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहा। अब जब नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक और व्यापार, आतंक और वार्ता, आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, तब पाकिस्तान दुनिया भर में सहानुभूति जुटाने निकला है। लेकिन दुनिया भी समझ रही है कि समस्या की जड़ कहां है।

पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पानी को लेकर युद्ध जैसे बयान देने वाले पहले अपने घर की हालत देखें। वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है और सेना तथा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भारत विरोध का सहारा ले रही हैं।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नया भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम भी उठाएगा। आतंकवाद को पालने वालों को अब हर क्षेत्र में जवाब मिलेगा। पाकिस्तान यदि वास्तव में शांति चाहता है तो उसे पहले आतंकवाद की फैक्टरी बंद करनी होगी। जब तक उसकी धरती से भारत विरोधी आतंक जारी रहेगा, तब तक कोई भी वार्ता केवल छलावा मानी जाएगी।

बहरहाल, भारत की जनता अब भ्रम में नहीं है। देश समझ चुका है कि शांति की सबसे पहली शर्त सुरक्षा है। और जो लोग पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। नया भारत अपने सैनिकों के खून का हिसाब भी लेगा और अपने पानी का अधिकार भी बचाएगा।

'इच्छाधारी' आस्था का चुनावी गणित

(प्रणय विक्रम सिंह)

अयोध्या के संदर्भ में विपक्ष की नई-नई जागी श्रद्धा को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है।

वे मारीच, सुबाहु और कालनेमि जैसे दिव्य भेष बदलने वाले मायावियों को त्रेतायुग में ही निपटा गए। उन्हें जरा रुकना चाहिए था। वे आज के युग में आते, तो देखते कि भेष बदलने की यह कला अब केवल राक्षसों की बपौती नहीं रही, इसका लोकतांत्रिक विकास हो चुका है और अब इसके सबसे कुशल अभ्यासकर्ता हमारे राजनेता हैं।

सुना है, कल तक जो लोग भगवान राम को केवल एक अदालती एफेडेविट का 'काल्पनिक पात्र' मानते थे, आज वे चुनाव की आहट सुनते ही हाथ में आस्था का नया-नवेला थर्मामीटर लेकर घूम रहे हैं। वे ट्विटर पर अयोध्या को 'अनुपम और अनुकरणीय धार्मिक नगरी' बनाने की वैसी ही पवित्र कसमें खा रहे हैं, जैसी कसमें एक जेबकतरा अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए कोट कचहरी में खाता है।

इस दिव्य और त्वरित हृदय परिवर्तन को देखकर मुझे गिरगिटों की मानसिक स्थिति पर तरस आता है। बेचारे डिप्रेशन में होंगे कि जिस हुनर के लिए वे सदियों से बदनाम थे, उसमें कुछ सैफई ब्रांड समाजवादी इंसानों ने पीएचडी कर ली और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा।

आखिर कोई उस राम-नाम का जाप इतनी पवित्रता से कैसे कर सकता है, जिसके राजनीतिक कुनबे का पूरा इतिहास ही राम-विरोध की खाद पर फला-फूला हो?

आजकल वे फीता लेकर निकले हैं। पूछ रहे हैं कि अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है? नेताजी, दूरी नापने का यह शौक नया है। पर आप गलत नक्शा देख रहे हैं। अयोध्या से गोरखपुर की दूरी तो उतनी ही है, जितनी सत्य और सनातन के बीच होती है। यानी दोनों आपस में जुड़े हैं। पर आपके 'पारिवारिक सिंडिकेट' और रामराज्य के बीच की दूरी अनंत है, जिसे नापने के लिए आपके पास न तो नैतिक पैमाना है और न ही वैसा चरित्र। अच्छा होता कि आप इस दूरी को नापने से पहले यह बता पाते कि राम के प्रति आपकी खानदानी नफरत और आपके वोटबैंक के लालच के बीच कुल कितने किलोमीटर का फासला है?

जब आदमी को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखती है, तो उसे इतिहास की कड़वी यादें भूलने का 'अल्जाइमर' रोग हो जाता है। लेकिन जनता की याददाश्त बहुत क्रूर होती है, नेताजी। जनता को आज भी याद है कि जब आपके पूज्य पिताजी की हुकूमत थी, तब अयोध्या की पावन गलियों में कोई भजन नहीं गूंज रहा था, बल्कि निहत्थे रामभक्तों का खून बह रहा था। तब आपकी सरकारी मशीनरी मंदिर के पत्थरों को ज़ब्त करने में वैसी ही मुस्तैदी दिखा रही थी, जैसी मुस्तैदी कोई डकैत माल समेटने में दिखाता है। और उसी पावन दौर में, पुलिस थानों और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पर ऐसा प्रतिबंध था, मानो कंस खुद लखनऊ के सचिवालय में आकर बैठ गया हो।

जो लोग कल तक रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र को अछूत मानकर ठुकरा रहे थे, आज वे 'सियाराम-धाम' के पुनरुद्धार का ठेका लेने की बात कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे बिल्ली चूहों की सुरक्षा के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाने का प्रस्ताव रखे।

राम की सेवा के लिए 'भेष' और 'ट्वीट' बदलने की नहीं, 'भाव' बदलने की जरूरत होती है। पर आपके पास तो वही पुराना हलफनामा है, जो आपने कभी सर्वोच्च न्यायालय में जमा किया था। आपकी पूरी राजनीतिक पूंजी ही यही रही है कि जब तक सत्ता में रहो, हिंदुओं की आध्यात्मिक भावनाओं को वैसे ही कुचलो जैसे रास्ते का कंकड़ कुचला जाता है, और जब चुनाव आ जाएं, तो माथे पर एक लंबा सा छद्म टीका लगाकर 'इच्छाधारी रामभक्त' की मुद्रा में जनता को सम्मोहित करने निकल पड़ो।

मेरी की एक बात हमेशा याद रखिएगा भैयाजी, आप भगवान को धोखा दे सकते हैं क्योंकि वे घट-घट वासी होकर भी चुप रहते हैं, पर जनता को नहीं, क्योंकि वह सब देखकर सही समय पर ईवीएम का बटन दबाती है।

सुना है, आपने तो अयोध्या का राजा ही बदल दिया। जबकि सभी सनातनियों के लिए त्रेता युग से आज तक अयोध्या के राजा श्री रामचन्द्र जी हैं। जो काम लंका का रावण अपनी पूरी दस खोपड़ियों की ताकत लगाकर नहीं कर पाया, वह आपने अपने वोटबैंक को खुश करने के लिए बड़ी सरलता से कर दिया। कई दिनों तक संसद में अपने बगल में उनको बैठाकर घुमाते रहे। राम से इतनी घृणा कि उन्हें अयोध्या के राजा के रूप में स्वीकार करने में आपकी छाती फटने लगती है, इसलिए आपने प्रतीकों का नया बाज़ार सजा लिया। आपका यह दोहरा चरित्र और अतीत उत्तर प्रदेश के हर रामभक्त के सीने में एक गहरे घाव की तरह आज भी टीस रहा है।

याद रखिए, इतिहास की स्याही बहुत पक्की होती है, वह आपके इन बनावटी और सुगठित ट्वीट्स के 'थूक' से नहीं धुलेगी। 10 नवंबर 1990 का वह अंधकारमय काला दिन, निहत्थों का रक्तपात, थानों में जन्माष्टमी पर पाबंदी और पावन पत्थरों का अपमान, यह सब आपके माथे पर वो अमिट कलंक हैं, जिन्हें धोने के लिए यदि आप सरयू का पूरा पानी भी इस्तेमाल कर लें, तो भी कम पड़ेगा।

अयोध्या अब सज चुकी है, दिव्य और भव्य हो चुकी है। वहां अब आपके पाखंड का कोहरा नहीं, बल्कि प्रभु राम का 'परम प्रकाश' जगमगा रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब प्रकाश उदित होता है।

ग्राम्य विकास के विरोध में विपक्ष !

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, जिसमें ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराया गया है, इसी समीक्षा की एक स्वाभाविक परिणति है। लेकिन यहां सहमति और असहमति के विकल्प भी हैं। संविधान में असहमति के बिंदु पर आगे जाने की व्यवस्था भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों को केंद्र में रखते हुए यह फैसला लिया था तो वह अपने संविधान सम्मत विकल्प भी देखेगी। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार इस न्यायिक निर्णय को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आतुर है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार ने एक प्रयास किया था कि किसी भी अवरोध पर गांवों का विकास अवरुद्ध न होने पाए।

(सुरेश बहादुर सिंह)

उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में ग्राम प्रधानों को भयभीत कर विपक्ष न सिर्फ नकारात्मक राजनीति का उदाहरण पेश कर रहा है, बल्कि ग्रामीण विकास में बाधा भी बन रहा है। यह साबित करता है कि जनाधार खो चुके राजनीतिक दल अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।)

एक बड़ा प्रश्न हम सबके समक्ष है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जवाब बहुत सारे हो सकते है, जैसे कि जनादेश सबसे बड़ी शक्ति है लेकिन बात पूरे लोकतंत्र की हो रही है। जनादेश यह तय करता है कि सत्ता किसकी होगी लेकिन जब लोकतंत्र के बारे में विचार करेंगे तो उसकी असली ताकत संविधान द्वारा निर्धारित संस्थाओं के बीच संतुलन और परस्पर सम्मान के रूप में उभरकर सामने आएगी। शासन जनता के विश्वास से चलता है, किंतु उसकी वैधता संविधान से आती है। इसलिए जब न्यायपालिका किसी प्रशासनिक निर्णय की संवैधानिक समीक्षा करती है, तो वह किसी सरकार की पराजय या विपक्ष की विजय का अवसर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वाभाविक प्रक्रिया है। दुर्भाग्य से आज न्यायालयों के निर्णय भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनते जा रहे हैं। फैसलों की कानूनी व्याख्या से अधिक उन्हें राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौला जा रहा है, जिससे समाज में भ्रम और अविश्वास का वातावरण पैदा होता है। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि न्यायिक निर्णयों को उनकी संवैधानिक भावना के अनुरूप समझा जाए, न कि राजनीतिक प्रचार के औजार के रूप में देखा जाए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, जिसमें ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराया गया है, इसी समीक्षा की एक स्वाभाविक परिणति है। लेकिन यहां सहमति और असहमति के विकल्प भी हैं। संविधान में असहमति के बिंदु पर आगे जाने की व्यवस्था भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों को केंद्र में रखते हुए यह फैसला लिया था तो वह अपने संविधान सम्मत विकल्प भी देखेगी। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार इस न्यायिक निर्णय को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आतुर है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार ने एक प्रयास किया था कि किसी भी अवरोध पर गांवों का विकास अवरुद्ध न होने पाए। जो विकास कार्य चल रहे हैं, वे रुकने न पाएं। इसमें सरकार का अपना पक्ष विकास का है।

न्यायालय का अपना पक्ष है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा प्रश्न इस बात का भी है कि विपक्ष के दायित्व क्या होने चाहिए थे। न्यायालय की गरिमा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब बात विकास की हो, ग्रामीण जनता के विकास की हो तो विपक्ष का उसमें राजनीतिक स्वार्थ देखना कितना न्यायोचित है, इस पर विचार करना होगा। ऐसे मुद्दों पर संकीर्णता को त्याग कर सरकार का सहयोग देना भी विपक्ष का लोकतांत्रिक कर्तव्य है। लेकिन, न्यायालय के आदेश को सही रूप में जनता तक पहुंचाने के बजाय विपक्ष ने भ्रम, भय और असत्य का एक ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया, जो न ग्राम प्रधानों के हित में है, न ग्रामीण समाज के और न ही इस देश के लोकतंत्र के।

यह समझना आवश्यक है कि विपक्ष कौन से भ्रम फैला रहा है और वास्तविकता क्या है। पहला और सबसे बड़ा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर असंवैधानिक कार्य किया। विपक्ष की मंशा यह स्थापित करने की है कि सरकार संविधान का उल्लंघन करने की मंशा से काम कर रही थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं, सरकार ने वही किया जो कोई भी जिम्मेदार व सजग संस्था करती। क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्राम प्रधान को ही प्रशासक बनाना सर्वाधिक उपयुक्त निर्णय था। फैसले की संवैधानिक व्याख्या एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है।

सरकारें प्रशासनिक निर्णय लेती हैं, न्यायालय उनकी संवैधानिक समीक्षा करता है और यदि न्यायालय किसी व्यवस्था को संविधान के अनुरूप नहीं पाता तो सरकार उस आदेश को स्वीकार करते हुए आवश्यक कदम उठाती है या अपने पक्ष को उचित मानते हुए बड़ी बेंच या शीर्ष अदालत तक जाती है। यही संवैधानिक लोकतंत्र की सुंदरता है और यही उसकी ताकत भी। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच यह संतुलन हमारे संविधान की आत्मा है। जब न्यायालय किसी व्यवस्था की संवैधानिक समीक्षा करता है तो इसका अर्थ यह है कि संवैधानिक व्याख्या का एक नया आयाम सामने आया है। आप सहमत हों तो स्वीकार करें या फिर इसे चुनौती दें।

कोर्ट के आदेश को केंद्र में रखते हुए एक भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि ग्राम प्रधानों द्वारा किए गए अब तक के सभी कार्य और भुगतान अवैध हो गए हैं। इसे इतने जोर-शोर से फैलाया जा रहा है मानो पिछले पांच सालों में गांवों में हुआ हर निर्माण कार्य, हर सड़क, हर नाली, हर सामुदायिक भवन अब गैरकानूनी हो गया हो। यह न केवल कानूनी दृष्टि से निराधार है, बल्कि अत्यंत गैरजिम्मेदाराना भी है। जब बात गांव के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की हो रही हो, तो उसमें विपक्ष का दायित्व है कि वह सकारात्मक रुख अपनाए। इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। राजनीतिक अटकलबाजी में वास्तविक तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

इस संदर्भ में एक और बात महत्वपूर्ण है जिसे विपक्ष सायास खड़ा कर रहा है। वह यह कि ग्राम प्रधानों से उनके कार्यकाल में खर्च किए गए धन की वसूली की जाएगी। विपक्ष यह भ्रम फैलाकर उन हजारों ग्राम प्रधानों के मन में भय व आतंक का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने ईमानदारी से अपने गांवों की सेवा की है। जो प्रतिनिधि सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में लगे रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर स्वच्छ भारत मिशन तक को गांव-गांव पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उन्हें भयभीत करना राजनीतिक दुर्भावना की पराकाष्ठा है।

एक सहज सवाल स्वाभाविक है कि विपक्ष यह भ्रम और भय क्यों फैला रहा है? इसके उत्तर में उन लोगों की प्रवृत्ति को देखना होगा, जिन्हें जनता खारिज कर चुकी है। जिन दलों के पास न कोई रचनात्मक नीति हो, न जनता के विकास का कोई ठोस दृष्टिकोण और न ही सत्ता में रहते हुए ग्रामीण उत्थान का कोई उल्लेखनीय इतिहास हो, उन्हें अदालती आदेश में अपने लिए संभावनाएं नजर आ रही हैं। अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए वे इसे भुनाने की चेष्टा करना चाहते हैं। ग्रामीण लोगों को भ्रमित करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार उनकी विरोधी है। वास्तविकता सबके सामने है। योगी सरकार में पंचायती राज संस्थाएं कितनी सशक्त हुई हैं, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। अदालत के आदेश पर कोई असंतुलित प्रतिक्रिया न देना न्यायपालिका के प्रति सरकार के सम्मान भाव का परिचायक है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध भी प्रतीत होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास बड़ी बेंच या शीर्ष अदालत में अपील का अधिकार भी है। पंचायतों के विकास कार्य किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दिए जाएं, यह उसकी प्रतिबद्धता भी है।

लोकतंत्र में न्यायालय की भूमिका संविधान के संरक्षक की है। जब वह किसी व्यवस्था की समीक्षा करता है और उसे परिमार्जित करने का निर्देश देता है, तो यह लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है। संवैधानिक संस्थाओं का सक्रिय रहना, सजग रहना, यह संदेश देता है कि वे अपने दायित्व निभा रही हैं। न्यायालय का सम्मान, संविधान की रक्षा और गांवों का निर्बाध विकास। इन तीनों को एक साथ चलना चाहिए और इसे सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। सुशासन न्यायपालिका का सम्मान करता है और जनता के हितों की सुरक्षा भी। इसलिए माना जा सकता है कि सरकार सुसंगत फैसले लेगी, संविधान सम्मत लेगी, जो विपक्ष के भ्रमजाल का जवाब भी होगा।

(लेखक पूर्व अपर शासकीय अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट) ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

सारंगढ़ की राजनीति को नई दिशा देने मे बिनोद का अहम योगदान... जनता के सुख-दुख में सदैव तत्पर, युवाओं की पहली पसंद..

सारंगढ़ के विकास का नया विकल्प - बिनोद भारद्वाज

सारंगढ़/मूक पत्रिका

राजनीति जब सेवा और कड़े संघर्ष का माध्यम बनती है, तो वह समाज को एक नई दिशा प्रदान करती है। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज एक ऐसे ही जुझारू, कर्मठ और लोकप्रिय युवा नेता की गूंज है, जिन्होंने अपने निस्वार्थ सेवा भाव से हर वर्ग के दिल में जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं विनोद भारद्वाज की, जिनका राजनीतिक सफर, राष्ट्रीय स्तर का संगठनात्मक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण आज सारंगढ़ की राजनीति के लिए एक मिसाल बन चुका है।

राष्ट्रीय नेतृत्व ने जताया भरोसा-बिनोद भारद्वाज जी की संगठनात्मक क्षमता का लोहा केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। कांग्रेस आलाकमान ने उनकी काबिलियत पर भरोसा जताते हुए उन्हें बिहार के वाल्मीकि विधान सभा चुनाव में अनुसूचित जाति विभाग की ओर से दिल्ली से मूल प्रभारी बनाकर भेजा था। अपनी कुशल रणनीति और दिन-रात की मेहनत के दम पर उन्होंने वहां बेहतरीन नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस विधायक ने वहां शानदार जीत दर्ज की। इस बड़ी जिम्मेदारी

को सफलतापूर्वक निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वे जमीनी स्तर पर चुनावी समीकरण बदलने का हुनर रखते हैं।

राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' में सक्रिय सहभागी-कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक 'भारत जोड़ो यात्रा' में भी बिनोद भारद्वाज जी ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। देश को एकजुट करने और नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने के इस महाअभियान में वे पूरी निष्ठा के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। राष्ट्रीय स्तर के इन बड़े आंदोलनों और सांगठनिक दौरों के अनुभवों का लाभ आज वे सारंगढ़ की जनता और स्थानीय संगठन को मजबूत करने में दे रहे हैं।

संघर्षों से तपा व्यक्तित्व- 04 जुलाई 1986 को जन्मे बिनोद भारद्वाज जी के जीवन का सफर आसान नहीं रहा। एक नौकरीपेशा पिता स्व0 अवध राम भारद्वाज के पुत्र होने के नाते उन्होंने हमेशा ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुना। पिता के असमय निधन के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। पिता की कमी आज भी उनके जीवन में खलती है, लेकिन उन्होंने इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया और जनसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ चले। इस पूरे सफर में उनके भाई राजेश भारद्वाज उनके सच्चे सारथी बनकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं।

स्कूल से शुरू हुआ नेतृत्व का सफर- बिनोद भारद्वाज जी के भीतर नेतृत्व के गुण छात्र जीवन से ही दिखाई देने लगे थे। उनका राजनीतिक सफर सारंगढ़ के प्रतिष्ठित मल्टी पर्पस स्कूल से शाला नायक का चुनाव जीतकर शुरू हुआ था। छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले बिनोद भारद्वाज ने तब से लेकर आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

सन 2001 से कांग्रेस के सच्चे सिपाही-पार्टी के प्रति वफादारी क्या होती है, यह विनोद भारद्वाज से सीखा जा सकता है। सन 2001 से लेकर आज तक, प्रत्येक परिस्थिति में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामे रखा है। एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पार्टी के लिए अपना तन, मन और धन हमेशा न्योछावर किया है। संगठन को हमेशा सर्वोपरि मानने वाले बिनोद जी ने सारंगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस मजबूती देने के लिए अपना सर्वश्व समर्पित कर दिया।

सारंगढ़ में राजनीति की परिभाषा बदल दी -2020 से पहले सारंगढ़ की राजनीति में नेताओं और जनता के बीच एक दूरी दिखाई देती थी, लेकिन बिनोद भारद्वाज ने इस परिपाटी को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी अनिका भारद्वाज को जिला पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाकर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी की एक नई शुरुआत की। आज सारंगढ़ विधानसभा के प्रत्येक गांव और मंडल में किसी के घर सुख हो या दुख, विनोद भारद्वाज एक नेता बनकर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में सबसे पहले खड़े नजर आते हैं। खेल-कूद से लेकर हर सामाजिक गतिविधियों में युवाओं को आगे बढ़ाने में वे हमेशा आगे रहते हैं। यही कारण है कि वे आज क्षेत्र की जनता के सबसे चहेते नेता बन चुके हैं।

भाजपा की लहर में भी अजेय रहे बिनोद -आज के दौर में जहां राजनीति की हवाएं तेजी से बदलती हैं, वहां बिनोद भारद्वाज ने वह कर दिखाया है जो बिरले नेता ही कर पाते हैं। पूरे प्रदेश और क्षेत्र में भाजपा की प्रचंड लहर होने के बावजूद, बिनोद भारद्वाज जी ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि अपनी मजबूत लोकप्रियता की ऐसी छाप छोड़ी कि विरोधी भी दंग रह गए। वे सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला पंचायत में एकमात्र कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य हैं जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है। राजनीति में एक बार जीतना किस्मत हो सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों और विरोधी लहर में दोबारा जीत हासिल करना केवल और केवल जनता के प्रति अटूट विश्वास, दिन-रात की मेहनत और मजबूत जमीनी पकड़ से ही संभव है। बिनोद जी की यह ऐतिहासिक जीत साबित करती है कि सारंगढ़ की जनता का उन पर कितना अटूट भरोसा है।

महिला आरक्षण की मांग को लेकर महिला कांग्रेस का जनजागरण अभियान

बीजापुर में पोस्टकार्ड, हस्ताक्षर और मिस कॉल अभियान चलाकर 33 फीसदी आरक्षण जल्द लागू करने की उठाई मांग

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में जनजागरण अभियान चलाया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लाम्बा के निर्देश पर आयोजित इस अभियान का नेतृत्व बीजापुर प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव तूलिका कर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान पोस्टकार्ड, हस्ताक्षर और मिस कॉल अभियान के माध्यम से महिलाओं ने अपनी मांग बुलंद की।तूलिका कर्मा ने कहा कि देश की आधी आबादी को राजनीति में समान भागीदारी देना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार

से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल को बिना विलंब लागू करने की मांग करते हुए कहा कि महिलाओं को निर्णय लेने वाली संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे ने कहा कि महिला आरक्षण लागू होने से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और नेतृत्व को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अभियान के दौरान महिलाओं ने पोस्टकार्ड के माध्यम से अपनी मांग दर्ज कराई, हस्ताक्षर कर समर्थन जताया तथा मिस कॉल अभियान के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। कार्यक्रम में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता कमल सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

कोटवारों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन,कोटवार संघ ने सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण की भी मांग उठाई

घरघोड़ा/रायगढ़/मूक पत्रिका

कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़, तहसील इकाई घरघोड़ा ने अपनी वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन घरघोड़ा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्गा प्रसाद अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान तहसीलदार मनोज गुप्ता एवं घरघोड़ा थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू भी मौजूद रहे। ज्ञापन में कोटवारों ने कहा कि वे ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और वर्षों से शासन-प्रशासन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते आ रहे हैं। गांवों में शासकीय सूचनाओं का प्रसारण, राजस्व विभाग के कार्यों में सहयोग, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता, प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाना सहित अनेक जिम्मेदारियां कोटवार निभाते हैं। इसके बावजूद उनकी वर्षों पुरानी मांगें

आज भी अधूरी हैं।संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से नियमितीकरण, सम्मानजनक वेतनमान, सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इससे प्रदेशभर के कोटवारों में असंतोष व्याप्त है।

कोटवारों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनकी सभी लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन एवं सेवा सुरक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही मांगों का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेशभर के कोटवार चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।ज्ञापन सौंपने के दौरान कोटवारों ने एकजुटता का परिचय देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य सरकार का ध्यान अपनी जायज मांगों की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करेंगे और वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे।

असर:ग्रामीण प्रशासन की सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले कोटवार अब अपने अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक मोड़ देने की तैयारी में हैं। यदि शासन ने समय रहते उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन पूरे प्रदेश में व्यापक रूप ले सकता है।

मांझीगुड़ा में योजना का किया निरीक्षण, किसानों से संवाद कर आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने का किया आह्वान

कृषि यंत्र बैंक से बदलेगी खेती की तस्वीर: रामविचार नेताम

बीजापुर/मूक पत्रिका

प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण एवं संबंधित विभागों के मंत्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को बीजापुर जिले के मांझीगुड़ा गांव पहुंचकर केंद्र सरकार की फार्म मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र बैंक) योजना का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसान योगेश बागड़े से मुलाकात कर कृषि यंत्र बैंक के संचालन और किसानों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कृषि यंत्रों की उपलब्धता, उपयोग और योजना के प्रभाव की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्र बैंक छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग से खेती की लागत घट रही है, श्रम की बचत हो रही है और उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने

अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाया जाए। साथ ही कृषि यंत्र बैंक के प्रति किसानों में जागरूकता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने गांव के किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से लगातार किसान हितैषी योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। दौरे के दौरान जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

सड़कों पर आवारा मवेशियों का डेरा, बढ़ रहा हादसों का खतरा

बकावंड/मूक पत्रिका

बकावंड विकासखंड की मुख्य एवं ग्रामीण सड़कों पर इन दिनों बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। सड़क के बीचों-बीच बैठे मवेशियों के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे वाहन चालकों, विशेषकर दोपहिया सवारों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।स्थानीय लोगों के अनुसार दिन के साथ-साथ रात के समय भी मवेशी सड़कों पर बैठे रहते हैं। अंधेरे में इनकी मौजूदगी वाहन चालकों को समय पर दिखाई नहीं देती, जिसके कारण अचानक टक्कर होने से लोग घायल हो रहे हैं। कई छोटे-बड़े हादसों में लोगों को चोटें आई हैं और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते आवारा मवेशियों को सड़कों से नहीं हटाया गया तो भविष्य में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, पशु मालिकों की जिम्मेदारी तय करने तथा सड़कों पर नियमित निगरानी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और आमजन की जान-माल की सुरक्षा बनी रहे।

रायगढ़ भाजपा में हर मनोनयन के बाद क्यों उठने लगते हैं विरोध के स्वर?, संगठन में नहीं सोशल मीडिया पर मुखर हो रहे भाजपाई

रायगढ़ /मूक पत्रिका

भाजपा कार्यालय में धीरे-धीरे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा था। कुछ ही देर पहले एल्डरमैनों की सूची जारी हुई थी। किसी के हाथ में मोबाइल था, कोई फेसबुक की पोस्ट पढ़ रहा था, तो कोई व्हाट्सएप स्टेटस दिखाकर राजनीतिक चुटकियां ले रहा था। जीत का उत्साह कम और चर्चाओं का बाजार ज्यादा गर्म था। इसी बीच एक पुराने कार्यकर्ता की धीमी आवाज कानों में पड़ी कि भाजपा कार्यालय में पहले संगठन की चिंता होती थी, कार्यकर्ताओं की बात होती थी। अब यहां फ्लाई ऐश, कोयला, कारोबार और राजनीतिक समीकरणों की चर्चा ज्यादा होती है।विदित हो कि यह केवल एक कार्यकर्ता की नाराजगी नहीं थी, बल्कि उस बदलती राजनीतिक संस्कृति का आईना थी, जिसकी चर्चा अब पार्टी के भीतर खुलकर होने लगी है।रायगढ़ भाजपा में यह पहला अवसर नहीं है, जब किसी

मनोनयन के बाद असंतोष सार्वजनिक हुआ हो। विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव के दौरान भी टिकट वितरण के बाद अनेक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ लिखा था। उस समय भी संगठन के भीतर दबे असंतोष ने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बाहर आने का रास्ता खोज लिया था।इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी खरसिया क्षेत्र के समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज रहीं। भाजपा युवा मोर्चा के तत्कालीन प्रदेशध्यक्ष रवि भगत के समर्थकों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। धीरे-धीरे उनका खेमा संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगा। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे पोस्ट सामने आने लगे, जिनमें निर्णय प्रक्रिया पर नाराजगी साफ झलकती थी।घटनाक्रम यहीं नहीं रुका। दो दिन पहले एक जुलाई को अपने जन्मदिन के दिन ही रवि भगत ने संगठन के पद से इस्तीफा दे दिया। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें संगठन की गतिविधियों और बैठकों में महत्व नहीं दिया जा रहा, न ही किसी जिम्मेदारी में शामिल किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस इस्तीफे की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि अगले ही दिन एल्डरमैनों की सूची सामने आ गई। इसके साथ ही एक बार फिर सोशल मीडिया पर असंतोष के स्वर तेज हो गए।

अब सवाल केवल किसी एक सूची या एक पद का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि आखिर भाजपा में लगभग हर बड़े मनोनयन के बाद विरोध की आवाजें सार्वजनिक क्यों होने लगी हैं? जिस दल की पहचान कभी अनुशासित संगठन और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया से होती थी, वहां अब असहमति सीधे सोशल मीडिया पर दर्ज होने लगी है।

सामाजिक और संगठनात्मक संतुलन पर उठे सवाल-रायगढ़ नगर निगम की घोषित एल्डरमैन सूची को लेकर भाजपा के भीतर और विभिन्न सामाजिक वर्गों में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। आरोप है कि सूची तैयार करते समय सामाजिक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक संतुलन की अनदेखी की गई। सबसे बड़ा सवाल महिलाओं की भागीदारी को लेकर उठ रहा है। केंद्र स्तर पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का समर्थन करने वाली भाजपा ने आठ एल्डरमैनों में एक भी महिला को स्थान नहीं दिया, जिससे संगठन की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल तब टूटता है जब एक व्यक्ति जिसने बीते चुनावों में भाजपा के खिलाफ काम किया और सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ जमकर लिखा आज वही पार्टी से एल्डरमैन बना है।सामाजिक समीकरणों को लेकर भी कई तरह की नाराजगी सामने आई है। आरोप है कि मारवाड़ी-ब्राह्मण वर्ग से दो नाम शामिल किए गए, जबकि इसी वर्ग का एक जनप्रतिनिधि पहले से मौजूद है। दूसरी ओर, शहर की राजनीति में प्रभावशाली माने जाने वाले मारवाड़ी समाज के अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर भी चर्चा तेज है।युवा कार्यकर्ताओं की नाराजगी का कारण यह भी है कि सूची में कुछ वरिष्ठ और पहले भी अवसर पा चुके चेहरों को दोबारा जगह मिली है। उनका सवाल है कि यदि नए कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलेगा तो संगठन में नई पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी-वहीं सिंधी समाज में भी एक नाम को लेकर असंतोष की चर्चा है। समाज के कुछ लोगों का आरोप है कि उनकी व्यापक सहमति के बजाय एक व्यक्ति को कथित रूप से संघ की पृष्ठभूमि के आधार पर प्राथमिकता दी गई। जबकि समाज के लोग जो लबे अरसे से पार्टी का परचम बुलंद किये हुए हैं और अपना सबकुछ पार्टी को दे दिया और पार्टी से क्या मिला धोखा। कुल मिलाकर, एल्डरमैनों की यह सूची अब राजनीतिक नियुक्ति से आगे बढ़कर सामाजिक प्रतिनिधित्व, महिला भागीदारी और संगठनात्मक संतुलन पर बहस का विषय बन गई है।

गुटबाजी चरम पर-कभी रायगढ़ भाजपा की ताकत उसका संगठन हुआ करता था। वरिष्ठ नेताओं के समय कार्यकर्ता मानते थे कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। निर्णय हर किसी के पक्ष में नहीं होते थे, फिर भी संवाद बना रहता था। आज कई पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि संवाद की जगह दूरी और संगठन की जगह गुटों ने ले ली है। भाजपा में जितनी गुटबाजी और खेमेबाजी आज है उतनी कभी नहीं थी। सभी दबी और सधी चाल चल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आयेंगे ऊपर से एक दिख रही पार्टी में भीतरघात और तेज़ हो जाएंगे। फिलहाल पार्टी एका के मुगालते में हैं।

रायगढ़ में दो दिवसीय नवीन आपराधिक कानून जनजागरूकता प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का शुभारंभ

स्कूली बच्चों ने स्टॉलों का भ्रमण कर नवीन कानून, साइबर सुरक्षा, यातायात एवं महिला सुरक्षा की ली जानकारी

DGPs/IGPs कॉन्फ्रेंस-2025 की सिफारिशों पर पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को मिला प्रशिक्षण

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने बच्चों से किया संवाद, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बढ़ाई कानूनी जागरूकता

कल 04 जुलाई को पुलिस जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन, जागरूकता प्रर्दशनी रहेगी जारी

रायगढ़ /मूक पत्रिका

=रायगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी के मार्गदर्शन पर रायगढ़ जिले में दिनांक 03 एवं 04 जुलाई को नवीन आपराधिक कानूनों के

प्रभावी क्रियान्वयन तथा आमजन में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दो दिवसीय जनजागरूकता प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का शुभारंभ किया जा रहा है । कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक मिश्रा, डीएसपी सुश्री उन्नति ठाकुर, एसडीओपी श्री सिद्धांत तिवारी, डीएसपी श्री उत्तम प्रताप सिंह एवं सुशांतो बनर्जी द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन-2025 (ष्ठत्रक्क्र/द्बत्रक्क्र ष्टश्ठद्गद्गह्लठ्ठष्द्ग-2025) की सिफारिशों के अनुरूप आधुनिक, तकनीक आधारित एवं जनकल्याणकारी पुलिसिंग विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य वक्ता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी ने बताया कि नवंबर 2025 में आईआईएम नया रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री तथा विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महा निरीक्षक शामिल हुए थे। सम्मेलन में थानों के आधुनिकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ढ्ढ), ष्टष्टञ्जहस्, द्बष्टछ्वस्, ढ्ढञ्जत्रद्भष्ठ, डेटा एनालिटिक्स, साइबर अपराध नियंत्रण, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग तथा ट्रस्ट-बेस्ड पुलिसिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। कार्यशाला में इन सिफारिशों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पुलिस व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने के संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।द्वितीय चरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी ने भारतीय न्याय संहिता (क्चहस्), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (क्चहस्स्) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (क्चस्न) सहित नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए कानूनों का उद्देश्य त्वरित एवं प्रभावी न्याय, पीड़ित-केंद्रित न्याय व्यवस्था, डिजिटल एवं तकनीक आधारित पुलिसिंग, महिलाओं एवं बच्चों की बेहतर सुरक्षा, संगठित अपराध, साइबर अपराध एवं आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण तथा समयबद्ध विवेचना एवं न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर नवीन कानूनों के अंतर्गत उपयोग में आने वाले नवीन प्रपत्रों तथा थाना एवं कार्यालयों में संधारित किए जाने वाले रजिस्टरों पर भी विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक मिश्रा ने पुलिसिंग में उपयोग किए जा रहे विभिन्न डिजिटल पोर्टलों की जानकारी दी, जबकि डीएसपी सुश्री उन्नति ठाकुर ने ष्टष्टञ्जहस् विषय पर अपना प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।कार्यशाला के दौरान स्कूली बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने बच्चों से संवाद कर आयोजन की रूपरेखा से अवगत कराया और बताया कि दो दिवसीय प्रदर्शनी में नवीन कानून, यातायात सुरक्षा, महिला सुरक्षा (हेलो सिस्टर हेल्पलाइन) एवं साइबर अपराध जागरूकता पर आधारित चार प्रमुख स्टॉल लगाए गए हैं। एसएसपी ने बच्चों को नए कानूनों की आवश्यकता, उद्देश्य एवं उनके व्यावहारिक महत्व के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का आयोजन में सहभागिता के लिए आभार भी व्यक्त किया। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने परिसर में लगाए गए सभी जागरूकता स्टॉलों का भ्रमण किया, जहां पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नवीन आपराधिक कानूनों, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, हेलो सिस्टर हेल्पलाइन तथा साइबर अपराध से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे और विशेषज्ञ अधिकारियों से उनके समाधान प्राप्त किए। आयोजन के दौरान बच्चों के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी सहित शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

श्रम विभाग में बड़ा घोटाला, भाजपा सरकार कर रही गरीबों के हक से खिलवाड़: ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षा व जनपद सदस्या शकुंतला श्रीवास

सारंगढ़-बिलाईगढ़ /मूक पत्रिका

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में श्रम विभाग और वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जनपद पंचायत बरमकेला की सदस्या एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी (महिला मोर्चा) की अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला श्रीवास ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ कागजों और दिखावे के शिविरों तक सिमट कर रह गई हैं, जबकि असल हितग्राही पिछले डेढ़ साल से दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

शिविरों के नाम पर धांधली और दिखावे की राजनीति :- कांग्रेस नेत्री शकुंतला श्रीवास ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा क्षेत्र में शिविर लगाकर भारी धांधली की जा रही है। इन शिविरों के माध्यम से केवल गिने-चुने और चहेते लोगों को चेक बांटकर वाहवाही लूटी जा रही है, जो कि पूरी तरह से एक दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में श्रम विभाग के भीतर एक बड़ा घोटाला पनप रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद श्रमिकों का हक मारा जा रहा है।

इन प्रमुख योजनाओं में आ रही हैं गंभीर शिकायतें :- शकुंतला श्रीवास ने विभाग की उन प्रमुख योजनाओं को रेखांकित किया, जिनमें हितग्राहियों को लंबे समय से लाभ नहीं मिल पा रहा है: मिनीमाता महतारी जतन योजनाः इसके तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 20,000 रुपए की राशि दी जानी है। आरोप है कि डेढ़ साल से महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिला है और गरीब महिलाएं अपने हक के पैसों के लिए भटक रही हैं। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना व गणवेश/पुस्तक योजनाः श्रमिकों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक की सहायता राशि का प्रावधान है, लेकिन यह भी अधर में लटका है।

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजनाः 59 से 60 वर्ष के बुजुर्ग श्रमिकों को मिलने वाली 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि से भी कई बुजुर्ग वंचित हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM)Ñ 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने वाली इस योजना का क्रियान्वयन भी लचर है।

जांच और नवीनीकरण ठप, डेढ़ साल से लंबित हैं आवेदनः- जनपद सदस्या ने आक्रोश जताते हुए कहा कि साइकिल सहायता योजना, प्रसूति योजना और मृत्यु सहायता योजना जैसे संवेदनशील मामलों की न तो कोई जांच की जा रही है और न ही कार्डों का नवीनीकरण हो रहा है। उन्होंने बताया: ÷क्षेत्र के सैकड़ों गरीब श्रमिकों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए बकायदा फॉर्म भरे हैं। फॉर्म भरे हुए डेढ़ साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक विभाग द्वारा उनका निराकरण नहीं किया गया। भाजपा सरकार श्रम विभाग के नाम पर गरीबों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही है।÷

निष्पक्ष जांच की मांग :- ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि श्रम विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया और लंबित पड़े आवेदनों का तुरंत निराकरण कर महिलाओं व श्रमिकों को उनका हक नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी श्रमिकों के हित में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उन्होंने शासन-प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

कटे होंठ और तालु की जन्मजात समस्या से मिली राहत, चिरायु दल की पहल से 15 वर्षीय बालक की हुई सफल सर्जरी

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत संचालित 'चिरायु' दल ने दूरस्थ क्षेत्र के एक 15 वर्षीय बालक को जन्मजात क्लेफ्ट लिप एवं पैलेट (कटे होंठ और तालु) की समस्या से निजात दिलाकर उसके चेहरे पर नई मुस्कान लौटा दी। शासन की निशुल्क उपचार व्यवस्था के चलते आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे का बिना किसी खर्च के सफल ऑपरेशन कराया गया। जानकारी के अनुसार उसूर विकासखंड के ग्राम मीनागट्टा (पामेड) निवासी माड़कम हुंगा जन्म से ही कटे होंठ और तालु की समस्या से पीड़ित था। इसके कारण उसे भोजन करने, स्पष्ट रूप से बोलने और सामान्य जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। आरबीएसके के चिरायु दल ने विद्यालय में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान बालक की पहचान की। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर उसे उच्चस्तरीय उपचार के लिए रेफर किया गया। बीएमओ और बीपीएम उसूर के मार्गदर्शन में 25 जून को बालक को रायपुर के श्री मेडिसिन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों ने क्लेफ्ट लिप एवं पैलेट की सफल प्लास्टिक सर्जरी की।सर्जरी के बाद चिकित्सकीय निगरानी में बालक के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ और 30 जून को उसे स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब वह पहले की तुलना में सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है।राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सर्जरी, जांच, दवाइयों, रायपुर तक आवागमन, उपचार अवधि के दौरान रहने और भोजन सहित पूरे इलाज का खर्च शासन ने वहन किया। इससे परिवार को किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरबीएसके के माध्यम से दूरस्थ और जरूरतमंद बच्चों की समय पर पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे गंभीर जन्मजात विकृतियों से पीड़ित बच्चों को नया जीवन और बेहतर भविष्य मिल रहा है।

मल्का पावर परियोजना विवाद पहुंचा कानूनी दहलीज तक, शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर!

धरमजयगढ़/मूक पत्रिका

बहुप्रतीक्षित मल्का जल विद्युत परियोजना से जुड़ा विवाद अब नए चरण में प्रवेश कर गया है। परियोजना संचालन से संबंधित शिकायतों और आरोप-प्रत्यारोप के बीच थाना धरमजयगढ़ पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद एक व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 एवं 115(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।जानकारी के अनुसार, धनवाड़ा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से थाना धरमजयगढ़ में एक विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में कंपनी प्रबंधन ने आरोप लगाया था कि परियोजना से पूर्व में जुड़े रहे एक व्यक्ति द्वारा कंपनी की गतिविधियों को प्रभावित करने, अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दबाव बनाने तथा परियोजना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है।और वहीं पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने के बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए तथ्यों और दस्तावेजों की जांच की। जांच प्रक्रिया के दौरान संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए। वहीं प्रारंभिक जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में कंपनी के एजीएम विवेक सिंह ने उल्लेख किया है कि रोहित राज श्रीवास्तव पूर्व में कंपनी से जुड़े लाइजनिंग कार्यों का दायित्व संभालते थे। कंपनी का दावा है कि वर्ष 2025 में उनकी कार्यशैली एवं व्यवहार से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते उन्हें कार्य से पृथक कर दिया गया था। इसके बाद से संबंधित व्यक्ति द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से आरटीआई आवेदन लगाकर कंपनी और कई शासकीय विभागों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया गया है।शिकायत में यह भी कहा गया है कि कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को कथित रूप से मानसिक दबाव में रखा जा रहा था तथा ग्रामीणों को भड़काकर विरोध का माहौल निर्मित करने की कोशिश की जा रही थी। कंपनी का दावा है कि यदि ऐसी गतिविधियां जारी रहती हैं तो परियोजना के संचालन और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका है।इधर, एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले ने और अधिक गंभीर रूप ले लिया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि विवेचना अभी जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल, मल्का पावर परियोजना से जुड़ा यह विवाद क्षेत्र का प्रमुख चर्चा विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें पुलिस एफआईआर के बाद आगामी कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं, जिससे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

जनपद सदस्य एवं किसान मोर्चा जिला महामंत्री राजू बेहरा के जन्मदिन पर मानकेश्वरी परिसर में हुआ वृहद पौधरोपण

रायगढ़ /मूक पत्रिका

रायगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय युवा नेता, जनपद सदस्य एवं किसान मोर्चा जिला महामंत्री श्री राजीव लोचन ÷राजू÷ बेहरा ने अपना जन्मदिन पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण कर मनाया। 2 जुलाई 2026 को मां जगदम्बा धाम मानकेश्वरी परिसर जामगांव में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। केक के बजाय पौधरोपण को दी प्राथमिकतापरंपरागत रूप से केक काटकर जन्मदिन मनाने के बजाय राजू बेहरा ने पौधरोपण को प्राथमिकता दी। वे विगत कई वर्षों से अपने प्रत्येक जन्मदिन पर वृक्षारोपण करते आ रहे हैं। पौधों की सुरक्षा और देखरेख के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था भी की जाती है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी इस सतत पहल ने पूर्वांचल क्षेत्र में उनकी अलग पहचान बनाई है।

सोशल मीडिया पर दिनभर छाए रहे राजू बेहरा- जन्मदिन के अवसर पर जिलेभर से युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीति से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से राजू बेहरा को शुभकामनाएं दीं। व्हाट्सएप, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिनभर बधाई संदेशों की भरमार रही। समर्थकों और शुभचिंतकों ने उनके पर्यावरण संरक्षण के संकल्प की सराहना करते हुए जन्मदिन को खास बनाया।

कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का जताया आभार- वृक्षारोपण एवं भोजन कार्यक्रम के पश्चात राजू बेहरा ने उपस्थित सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं देने वाले साथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि व्यस्त समय में भी सभी का स्नेह, सहयोग और सहभागिता उनके लिए दोगुनी खुशी का कारण बनी है।

बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता रहे उपस्थित- कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री पावन अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष संजय नायक, मंडल अध्यक्ष मिनकेतन प्रधान, महामंत्री मुरारी अग्रवाल, छवि पटेल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुषमा खलखो, रमेश बेहरा, जनपद पंचायत सीईओ, पार्षद अशोक यादव, आनंद भगत, मनोज प्रधान, जनपद सदस्य सुखलाल चौहान, जयंत प्रधान, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ललित यादव, महामंत्री दीपक गुप्ता, गौरांग साव, रघुनाथ कौंध, सतवीर सिंह, घनश्याम पटेल, नूतन पटेल, शशिभूषण नायक, चरण भारती, राजेंद्र डनसेना, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रामश्याम डनसेना, ओंकार तिवारी, दुष्यंत रात्रे, विद्या नायक,लाभों साहू एवं परमानंद सारथी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रत्येक दिन 8 ग्राहक करा रहे पीएम सूर्य घर का सेटअप इंस्टॉलेशन, विभागीय स्टॉफ, बैंकर्स, वेंडर्स और बिहान सदस्य के सामूहिक योगदान से मिल रहा हितग्राहियों को लाभ

1700 हितग्राहियों ने किया 5 लाख 88 हजार यूनिट बिजली उत्पादन, मिला 25 लाख 80 हजार रूपये का मुफ्त बिजली

सारंगढ़ बिलाईगढ /मूक पत्रिका

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों में तेजी आई है। कलेक्टर के द्वारा बैंकर्स और वेंडर्स का संयुक्त बैठक और बिहान के महिला सदस्यों को प्रशिक्षित कर कार्य में शामिल करने से रिजल्ट अच्छा आने लगा है। योजना के क्रियान्वयन में तेजी आई है। सभी वेंडर्स लक्ष्य की प्रगति में कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के महिला सदस्यों के द्वारा मौखिक प्रचार, कार्यपालन अभियंता विद्युत प्रकाशचंद महानंदा और जिले के ऊर्जा विभाग के सभी विद्युतकर्मी, सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास और योगदान से प्रतिदिन 8 ग्राहक के घर में पीएम सूर्य घर का सेटअप इंस्टॉलेशन किया जा रहा है।सभी इच्छुक सरकारी कर्मियों के अलावा पंचायत एवं

ग्रामीण विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मियों द्वारा भी इस योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऊर्जा विभाग द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को 4312 कनेक्शन स्थापित करने का लक्ष्य मिला है। जिले में अब तक 1700 से अधिक हितग्राही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। हितग्राहियों के द्वारा 5 लाख 88 हजार यूनिट उत्पादन किया गया है, जिससे हितग्राहियों को 25 लाख 80 हजार रूपये का सीधा लाभ मिला है। विगत अप्रैल, मई और जून माह में हितग्राही के घरों, प्रतिष्ठानों और शासकीय तथा निजी कार्यालयों में 550 से अधिक सेटअप स्थापित किया जा चुका है। 780 हितग्राहियों के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मांग को विभाग और वेंडर द्वारा पूरा किया जा रहा है। सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिले के नागरिक इस योजना के माध्यम से अब वास्तव में ÷ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत÷ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

1 से 3 किलोवाट सोलर से लाभ- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक लाख 8 हजार रूपये का अनुदान सीधे उनके बैंक खाता में भुगतान किया जाता है। इस योजना से बिजली बिल कम और नवीन रोजगार सृजन होगा तथा अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। 1 किलोवाट रूफ टॉप सोलर क्षमता का संयंत्र स्थापित कराने पर कुल लागत 60 हजार का लागत आएगा, जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से 30 हजार का अनुदान और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 15 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को अपने घर में पीएम सूर्य घर का सेटअप लगाने के लिए न्यूनतम 15 हजार रूपए नगद या बैंक ऋण (लोन) के माध्यम से भुगतान करना होगा। 2 किलोवाट रूफ टॉप सोलर क्षमता का संयंत्र स्थापित कराने पर कुल लागत 1 लाख 20 हजार का लागत आएगा, जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से 60 हजार का अनुदान और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 30 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को अपने घर में पीएम सूर्य घर का सेटअप लगाने के लिए न्यूनतम 30 हजार रूपए नगद या बैंक ऋण (लोन) के माध्यम से भुगतान करना होगा। 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर क्षमता का संयंत्र स्थापित कराने पर 1 लाख 80 हजार का लागत आएगा, जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से 78 हजार रूपए और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 30 हजार रूपए का अनुदान मिलेगा। इसके लिए हितग्राही को अपने घर में पीएम सूर्य घर का सेटअप लगाने के लिए न्यूनतम 72 हजार रूपए नगद या बैंक ऋण (लोन) के माध्यम से भुगतान करना होगा।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया- प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल है। उपभोक्ता स्वयं पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन pmsuryaghar.gov.in पोर्टल, पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप या टोल फ्री नंबर 1912 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता अपने पसंद के वेंडर का चयन ऑनलाइन कर सकते हैं और सोलर पैनल स्थापना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी कर सकते हैं। यह योजना न केवल बिजली बिल में हर महीने हजारों रुपये की बचत करा रही है, बल्कि हितग्राहियों को हरित ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरित भी कर रही है।

सरसीवां में पर्यावरण अनुकूल पहलः सौमित्र फ्यूल्स पर शुरू हुआ क्षेत्र का पहला अत्याधुनिक 'HP eCharge' फास्ट चार्जिंग स्टेशन

सारंगढ़ बिलाईगढ /मूक पत्रिका

क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरसीवां स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिष्ठित रिटेल आउटलेट 'सौमित्र फ्यूल्स' में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस सुविधा के शुरू होने से अब क्षेत्र के साथ-साथ मुख्य मार्ग से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग की चिंता से बड़ी राहत मिलेगी।

'FAME योजना के तहत स्थापित हुआ 'HP eCharge' फास्ट चार्जर :-सौमित्र फ्यूल्स में स्थापित यह चार्जिंग पॉइंट भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय योजना के अंतर्गत तैयार किया गया है। यह एक 'HP eCharge' फ़ास्ट चार्जर है, जिसे प्रमुख ऊर्जा कंपनी 'सूर्या' के सहयोग से स्थापित किया गया है। फास्ट चार्जर होने के कारण यहाँ वाहन बेहद कम समय में चार्ज हो सकेंगे, जिससे लंबी दूरी का सफर तय करने वाले चालकों के समय की भारी बचत होगी।

इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत :- अब तक सरसीवां और आसपास के ग्रामीण अंचलों में पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण लोग इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर या टू-व्हीलर खरीदने से कतराते थे, या फिर उन्हें केवल घरेलू चार्जिंग पर ही निर्भर रहना पड़ता था। सौमित्र फ्यूल्स पर इस कमर्शियल फास्ट चार्जिंग पॉइंट के शुरू होने से अब स्थानीय स्तर पर पर्यावरण अनुकूल वाहनों के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ेगा।

मुख्य मार्ग पर सफर होगा और आसान :-यह आउटलेट मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण अन्य शहरों या राज्यों से आने-जाने वाले ईवी चालकों के लिए एक प्रमुख 'चार्जिंग हॉल्ट' के रूप में उभरेगा। डिजिटल डिस्प्ले और अत्याधुनिक सुरक्षा मानकों से लैस यह मशीन पूरी तरह से यूजर-फ्रेंडली है, जहां डिजिटल पेमेंट के माध्यम से बेहद आसानी से वाहनों को चार्ज किया जा सकता है।

सौमित्र फ्यूल्स के इस आधुनिक और दूरदर्शी प्रयास की स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। लोगों का कहना है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इस तरह की तकनीकों का आना क्षेत्र के विकास की नई तस्वीर को दर्शाता है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में चिकित्सा जगत शर्मसारः मरीजों को 'प्रायोगिक चूहा' बनाकर चल रहा है झोलाछापों का प्रशिक्षण; यूनानी विभाग की ब्लैकलिस्ट के बाद भी अफसरों का 'मौन संरक्षण' जारी

विशेष खोजी रिपोर्ट –स्वास्थ्य के नाम पर 'सफेदपोश यमदूतों' का साम्राज्य

सारंगढ़ बिलाईगढ /मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक ईमानदारी पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ चुकी है। जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक चिकित्सा के नाम पर जो खौफनाक खेल खेला जा रहा है, उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। जिले में कुकुरमुत्ते की तरह खुले अवैध क्लीनिक न केवल लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि बिना योग्यता और पंजीयन के एक समानांतर और जानलेवा स्वास्थ्य व्यवस्था चला रहे हैं।सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि इस पूरे काले साम्राज्य की मुकम्मल जानकारी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ष्टरू॥ह्र), विकासखंड चिकित्सा अधिकारी (क्चरूह्र) और स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में है। इसके बावजूद, जिम्मेदार अधिकारियों का इस कदर मौन रहना यह साफ गवाही देता है कि सिस्टम के भीतर बैठे कुछ रसूखदार सफेदपोशों की शह पर ही इन अवैध

डॉक्टरों की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं।

परत दर परत खुलासाः इलाज कम, इंसानी जिंदगियों पर 'प्रशिक्षण' ज्यादा :- इस पूरे गोरखधंधे की सबसे खौफनाक और रूह कंपा देने वाली सच्चाई यह है कि ये फर्जी डॉक्टर मरीजों का इलाज कम करते हैं, बल्कि उन पर डॉक्टरी का 'प्रशिक्षण' (सीखने का काम) ज्यादा करते हैं।

***1. मासूम जनता बनी 'प्रायोगिक चूहा':-** चूंकि इन तथाकथित डॉक्टरों के पास कोई वैध मेडिकल डिग्री या ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए ये क्लीनिक में आने वाले भोले-भाले ग्रामीण मरीजों को 'प्रायोगिक चूहा' समझ लेते हैं। नस खोजना हो, बोतल चढ़ाना हो, टांके लगाने हों या फिर गंभीर इंजेक्शन देना हो–ये झोलाछाप बिना किसी ज्ञान के मरीजों के शरीर पर हाथ आजमाते हैं और ककहरा सीखते हैं। इनके इस ÷सीखने-सिखाने÷ के चक्कर में न जाने कितने मरीजों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, गलत दाद-खाज के इलाज में चमड़ी सड़ जाती है, और अंततः लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

2. अवैध गर्भपात और खतरनाक लाइफ सपोर्ट का खेलः- सूत्रों के मुताबिक, इन फर्जी क्लीनिकों के बंद कमरों में धड़ल्ले से अवैध गर्भपात का काला कारोबार संचालित होता है। बिना किसी सर्जिकल विशेषज्ञता के, ये झोलाछाप डॉक्टर केवल 'तुक्के' और 'अनुमान' के आधार पर महिलाओं की जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन टेबल पर बैठ जाते हैं और सर्जरी करना ÷सीखते÷ हैं। जब स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है और मरीज तड़पने लगता है, तब अपनी खाल बचाने के लिए उसे आनन-फानन में अन्य राज्यों या बड़े निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, और अधिकांश मामलों में मासूम जिंदगियां रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं।

3. आधुनिक और अवैध उपकरणों का दुरुपयोग :- जिले के बिलाईगढ़, सारंगढ़, सरसींवा, भटगांव और सलीआर जैसे इलाकों में सक्रिय इन डॉक्टरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये अपनी दुकानों में बड़े-बड़े आधुनिक और अवैध डॉक्टरी उपकरण (जैसे पोर्टेबल एक्स-रे, सोनोग्राफी मशीनें और अवैध पैथोलॉजी लैब) लगाकर बैठे हैं। इन तकनीकी मशीनों को चलाने का कोई सर्टिफिकेट न होने के बावजूद, ये केवल अनुमान के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं और गलत डायग्नोसिस कर मरीजों को मौत के मुहाने पर धकेल देते हैं।

***बड़ा दस्तावेजः यूनानी विभाग की 'ब्लैकलिस्ट' को रद्दी का टुकड़ा समझकर ठेंगा दिखा रहे झोलाछाप :-** यह कोई हवा-हवाई आरोप नहीं है कि प्रशासन को इसकी खबर नहीं है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रशासनिक विरोधाभास और ढोंग तब उजागर होता है, जब हम अतीत के पन्नों को पलटते हैं।दस्तावेजी सबूतः कुछ समय पूर्व जिला यूनानी व आयुर्वेद चिकित्सा विभाग द्वारा जिले में सक्रिय फर्जी क्लीनिकों और बिना योग्यता के यूनानी/आयुर्वेदिक पद्धतियों की आड़ में एलोपैथिक इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों की एक बाकायदा 'आधिकारिक ब्लैकलिस्ट (सूची)' जारी की गई थी। इस सूची में दर्जनों ऐसे डॉक्टरों और क्लीनिकों के नाम, पते और उनके द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े का पूरा ब्यौरा दर्ज था।

कागजों पर कार्रवाई, जमीन पर खुली छूटः- कागजी नियमों के अनुसार उस सूची के जारी होने के तुरंत बाद इन सभी फर्जी क्लीनिकों को सील किया जाना था और संबंधित जालसाजों को सलाखों के पीछे भेजा जाना था।

लेकिन सारंगढ़-बिलाईगढ़ के स्वास्थ्य विभाग का रवैया देखिए–वह सूची आज भी सरकारी फाइलों में धूल खा रही है। जिन डॉक्टरों को खुद सरकारी विभाग ने 'फर्जी' और 'अवैध' घोषित किया था, वे आज पहले से भी ज्यादा ठाट-बात और बेखौफ अंदाज में अपनी दुकानें चला रहे हैं। क्या यह सीधे तौर पर कानून का मखौल उड़ाना नहीं है? क्या यह साबित नहीं करता कि यूनानी विभाग की वह लिस्ट सिर्फ दिखावे के लिए थी, ताकि जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सके?

देशभर की मिसालेंः जब-जब फूटा फर्जी क्लीनिकों का भंडाफोड़ः- सारंगढ़-बिलाईगढ़ की यह भयावह स्थिति कोई पहली घटना नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में जब प्रशासन ने अपनी आंखें मूंदीं, तो इसी तरह इंसानी जिंदगियों पर प्रैक्टिकल करने वाले गिरोहों का साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसके बाद न्यायपालिका और पुलिस को कड़े कदम उठाने पड़ेः 1.हापुड़ और मेरठ (उत्तर प्रदेश) का नर्सिंग होम कांडः उत्तर प्रदेश के मेरठ और हापुड़ जिलों में इलाज की आड़ में चल रहे अवैध नर्सिंग होम और क्लीनिकों पर जब छापेमारी हुई, तो वहां बड़े पैमाने पर बिना पंजीकरण के चल रहे ऑपरेशन और अवैध चिकित्सा पद्धतियों का खुलासा हुआ था। वहां हाईकोर्ट के कड़े रुख के कारण दर्जनों क्लीनिकों को ध्वस्त किया गया और दोषी स्वास्थ्य अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी। 2.मुंबई (महाराष्ट्र) का झोलाछाप विरोधी अभियानः मुंबई के उपनगरीय इलाकों (जैसे गोवंडी और मानखुर्द) में पुलिस और बीएमसी (क्चरूष्ट) की संयुक्त विंग ने 'बोगस डॉक्टर्स' के खिलाफ मकोका (रूष्टह्रष्ट) जैसी सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। वहां भी इन अवैध क्लीनिकों का इस्तेमाल मरीजों पर गलत दवाइयों के ट्रायल और नकली दवाइयां बेचने के लिए किया जा रहा था।

सहकार से सरोकार : वृक्षारोपण, स्वच्छता और कृषक जागरूकता से गूंजा बस्तर का ग्रामीण अंचल

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर ने सहकारी सप्ताह में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और किसान हितैषी योजनाओं को दिया नया विस्तार

सहकारिता केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के निर्वहन का भी सशक्त मंच - दिनेश कश्यप

जगदलपुर/मूक पत्रिका

पवन कुमार नाग । जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर द्वारा सहकारी सप्ताह के अंतर्गत आज ÷सहकार से सरोकार : स्वच्छ गाँव, समृद्ध पर्यावरण÷ थीम पर बाबुसेमरा, माड़पाल एवं करपावण्ड में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान एवं कृषक संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। निर्धारित कार्यक्रमों के अनुरूप संपन्न इस आयोजन ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता जागरूकता और किसान हितों को एक साथ जोड़ते हुए सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष दिनेश कश्यप द्वारा वृक्षारोपण कर किया गया। इस दौरान उन्होंने किसानों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अधिकाधिक वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के निर्वहन का भी सशक्त मंच बन चुकी है।आयोजित कृषक संगोष्ठी में किसानों को सहकारी योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड (चष्ष्ट), ऋण सुविधा, खाद-बीज वितरण तथा अन्य किसान हितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर किसानों को कृषि क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका एवं उससे मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूक किया गया।कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ग्रामीणों के साथ पौधारोपण किया गया तथा प्लास्टिक मुक्त वातावरण और स्वच्छ ग्राम निर्माण के लिए प्रेरित किया गया।

स्वच्छता अभियान के माध्यम से गांवों में स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संतुलन की दिशा में जनभागीदारी का संदेश दिया गया। इस अवसर पर सहकारिता प्रकोष्ठ से रंजीत पाण्डेय, जिला संयोजक मनोहर दत्त तिवारी, सह संयोजक संतोष नाग, सहकारिता विभाग से उप आयुक्त एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला बस्तर, के.एन. पाण्डेय, अध्यक्ष आदर्श सहकारी मुद्रणालय तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ, जनपद अध्यक्ष, सरपंच, सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी, किसान विजय भारत, शिव जी सहित क्षेत्र के अन्य किसान एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित. के अतिरिक्त प्रबंधक एस. ए. रज़ा ने सभी अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं उपस्थित किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने तथा किसानों को इससे जोड़ने का संकल्प दोहराया। सहकार से सरोकार : स्वच्छ गाँव, समृद्ध पर्यावरण÷ की भावना के अनुरूप आयोजित यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और किसान जागरूकता के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी और महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

न्योता भोज में बच्चों के साथ किया भोजन

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू एवं उप मुख्यमंत्री अरुणसाव ने नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर किया आत्मीय स्वागत

- जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर दिया गया जोर

बिलासपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज यहां सेजेस लाल बहादुर शास्त्री, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर स्थित देवकीनंदन दीक्षित सभागार में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कर आत्मीय स्वागत किया। अतिथियों ने बच्चों के साथ न्योता भोज में शामिल होकर भोजन किया एवं छात्राओं का सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकल का वितरण भी किया। उन्होंने नए शिक्षा सत्र के शुभारंभ पर विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने, संस्कारवान नागरिक बनने और अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा प्रदेश का नाम रोशन करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पांडे, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता संतोष कश्यप, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अंबिका साहू, पूर्व महापौर श्री किशोर राय, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल,

जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामेश्वर जायसवाल, श्री दीपक सिंह, श्री मोहित जायसवाल, राजेश सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, पालक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं पालकों को नए शिक्षा सत्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शाला प्रवेशोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का उत्सव है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी प्राथमिक पाठशाला की स्मृतियां हमेशा बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छे संस्कार और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूरे मन से अध्ययन कर अपने परिवार, समाज, प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार कर रही है। आज स्कूलों में भवन, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में सम्मानपूर्वक आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है।

ओप्पो इंडिया ने रेनो 16 सीरीज पेश की, जिसमें क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए है ए.आई पोर्ट्रेट कैमरा और ए.आई रीमिक्स कोलाज

नई दिल्ली: आज ओप्पो इंडिया ने अपनी रेनो 16 सीरीज लॉन्च की। इस सीरीज में भारत के पहले होलोवर्स 3डी डिजाईन, 50 मेगापिक्सल के मेन और 3.5एक्स टेलीफोटो लेंस वाले ए.आई पोर्ट्रेट कैमरा, नैचुरल टोन इमेजिंग और ऑल-फोकल-लेंथ 4के 60एफ्पीएस एचडीआर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ दो स्मार्टफोन रेनो 16 और रेनो 16सी पेश किए गए हैं। ये स्मार्टफोन युवाओं के लिए बनाए गए हैं। रेनो 16 सीरीज केवल एक कम्युनिकेशन डिवाईस नहीं, बल्कि कैमरा और क्रिएटिव स्टूडियो के साथ प्रोडक्टिविटी कंपेनियन और पर्सनल असिस्टेंट भी है। रेनो 16 सीरीज में जहाँ शानदार कंटेंट के लिए ए.आई रीमिक्स कोलाज, पॉप कैम और पॉपआउट 2.0 जैसे ए.आई पॉवर्ड टूल हैं, वहीं लेटेस्ट कलरओएस 16 की मदद से बहुत ही इंटैलिजेंट अनुभव भी मिलता है। इसलिए रेनो 16 सीरीज के साथ यूजर आसानी से क्रिएट, कनेक्ट और एक्सप्रेस करने में समर्थ बनते हैं।

गोल्डी पटनायक, हेड, पीआर एंड कम्युनिकेशंस, ओप्पो इंडिया ने कहा, ''आज की पीढ़ी के लिए स्मार्टफोन केवल एक डिवाईस नहीं है, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी दिखाने और कहानियों एवं व्यक्तित्व को कैप्चर करने के लिए हमेशा उनके साथ रहने वाला कंपेनियन भी है। रेनो सीरीज हमेशा से ट्रेंडसेटिंग डिजाईन के साथ बेहतरीन इनोवेशन पेश करती आई है। यह सीरीज वैसे ही आगे बढ़ी है, जैसे युवा क्रिएट और कनेक्ट करते हैं। रेनो 16 सीरीज के साथ हम अब तक का सबसे एक्सप्रेसिव डिजाईन लेकर आए हैं। इसमें अभी तक का सबसे इंटैलिजेंट कैमरा अनुभव और ए.आई दिया गया है, जो बैकग्राउंड में काम करते हुए हर क्रिएटिविटी को आसान बना देता है। रेनो 16 सीरीज में हर इनोवेशन को सोच समझकर यूजर्स के लिए विकसित किया गया है। यह सीरीज उन्हें महत्वपूर्ण क्षणों को कैप्चर करने, खुद को एक्सप्रेस करने और प्रीमियम अनुभवों का आनंद लेने में समर्थ बनाती है।

भारत का पहला होलोवर्स 3डी डिजाईन- रेनो की हर जनरेशन एक नए डिजाईन के साथ आती है। रेनो 16 में इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब तक का सबसे बोल्ड एक्सप्रेशन दिया गया है। यह कॉस्मोस की सुंदरता और रहस्य से प्रेरित है। रेनो 16 सीरीज के साथ भारत में पहला होलोवर्स 3डी डिजाईन पेश किया गया है, जो ओप्पो की एक्सक्लुसिव होलोवर्स 3डी टेक्नोलॉजी से बना है। इसमें ऑल-न्यू 3डी पॉप प्लैनेट डिजाईन है, जो एक ऐसा स्मार्टफोन बनाता है, जो हर एंगल से खास है

3डी पॉप प्लैनेट डिजाईन केवल स्टैरी व्हाईट वैरिएंट में उपलब्ध है। यह एक आकर्षक नैकेड-आई 3डी इफेक्ट पैदा करता है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि फोन की सतह के नीचे अंतरिक्ष के प्लैनेट फ्लोट कर रहे हैं। यह डिजाईन प्रेसिजन-इंजीनियर्ड ड्युअल-लेयर ऑप्टिकल स्ट्रक्चर और लाखों माईक्रो लेंस से बना है। जैसे ही प्रकाश और जगह को बदला जाता है, इस डिजाईन में हर दिशा से गहराई और मूवमेंट उभरकर आते हैं। इस सिग्नेचर लुक के साथ ओप्पो का फ्लोटिंग 3डी ग्लिटर फिनिश और डायनामिक स्टेलर रिंग भी है, जो कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर चमक और डेप्थ उत्पन्न करता है, जिससे इसे एक खास विज्युअल पहचान मिलती है। ये स्मार्टफोन वन-पीस कोल्ड-स्कल्पटेड डिजाईन से बनाए गए हैं। रेनो 16 और रेनो 16सी स्टैरी व्हाईट, ट्वाईलाईट वॉयलेट और स्टेलर पर्पल रंगों में उपलब्ध होंगे, जो हाथों में प्रीमियम लुक के साथ आपके व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति को बेहतर बनाएंगे।

डीएमएफ से बदली खनन प्रभावित गांवों की तस्वीर

- मुढ़ापार-कोरबी सड़क बनी विकास की नई पहचान
- कलेक्टर कुणाल दुदावत ने डीएमएफसे जिले के विकास के लिए की है प्लानिंग

कोरबा। जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों के विकास में बड़ी बाधा बना हुआ था। गांवों की जर्जर सड़कें, विशेषकर वर्षा ऋतु के दौरान, लोगों की परेशानी का प्रमुख कारण थीं। आवागमन बाधित होने से विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने, मरीजों को अस्पताल जाने, किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने तथा ग्रामीणों को दैनिक आवश्यक कार्यों के लिए अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार सड़क पर कीचड़ और जलभराव के कारण लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता था। इन समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन्हीं विकास कार्यों में ग्राम मुढ़ापार से धतूरा होते हुए कोरबी एवं खम्हरिया तक सड़क के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल किया गया। यह लगभग 4.40 किलोमीटर लंबी सड़क वर्षों से अत्यंत जर्जर स्थिति में थी। बरसात के मौसम में पूरी सड़क कीचड़ से भर जाती थी, जिससे ग्रामीणों का आवागमन लगभग ठप हो जाता था। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं माननीय विधायक श्री प्रेमचंद पटेल द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए इस सड़क के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की मांग जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। ग्रामीणों की इस बहुप्रतीक्षित मांग को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से 180.93 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। निर्माण एजेंसी ने निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए 15 अप्रैल 2026 को सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया।

एसईसीएल सुराकछार खदान में कबाड़ चोंरों ने लगाई सेंध

सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमला कर डकैती की घटना को दिया अंजाम, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

कोरबा। जिले में कबाड़ माफ्रिया का नेटवर्क लगातार बेखौफ होता जा रहा है। पुलिस कप्तान की सख्ती और जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में एक कबाड़ माफ्रिया के अवैध आलीशान मकान पर बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई के बावजूद अपराधियों में कानून का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र का है, जहां एसईसीएल की सुराकछार भूमिगत खदान में दो दर्जन से अधिक हथियारबंद कबाड़ चोरों ने धावा बोलकर डकैती की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सुरक्षाकर्मियों के साथ बेरहमी से मारपीट कर एक कर्मी से मोबाइल फोन और नकदी ली। और फिर खदान से कीमती कॉपर केबल काटकर फरार हो गए। इस पूरी घटना ने एक बार फिर बांकी मोंगरा पुलिस की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा करने के साथ ही जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि एसईसीएल की सुराकछार भूमिगत में शुक्रवार 26 जून की देर रात दो दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाश घुस गये। घटना के वक्त सुराकछार के 3-4 नंबर खदान में सुरक्षाकर्मी परमात्मा, चेतन, जयपाल, विश्वनाथ राठौर, लक्ष्मीनारायण नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर थे। खदान में घुसने के बाद कबाड़ चोरों ने इन सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया और मारपीट के बाद बंधक बना लिया। सुरक्षाकर्मी को घायल करने के बाद कबाड़ चोर खदान के हाजिरी बाबू विश्वनाथ राठौर के केबिन में पहुंचकर मोबाइल और पर्स में रखे 4500 रुपये लूट लिए। वहीं घायल सुरक्षाकर्मियों को दूसरे दिन सुबह विभागीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घायल सुरक्षाकर्मियों के मुताबिक घटना के बाद कबाड़ चोर खदान परिसर से कीमती केबल लेकर फरार हो गये।

जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी चार दिन से उपभोक्ताओं कि समस्याओं का नहीं कर पा रहें निराकरण।

सुशासित तेवहार आयोजित कर जहाँ सुनी गई जानता की समस्या, वही की जनता चार दिन से बिजली कटौती से है त्रस्त,ओड़ेकरा

सक्ती/ जैजैपुर/मूक पत्रिका

जिले के जैजैपुर सबस्टेन अंतर्गत आने वाले ओड़ेकेरा फ़िटर में आधा दर्जन गांव लोग बीते चार दिन से बिजली विभाग के ख़राब कार्य प्रणाली से जूझ रहे है और ग्रामीण अंधेरे में डूबे हुए हैं। जिसका सुध लेने वाला कोई नहीं हैं, यहाँ सुधार के नाम पर उपभोक्ता को गुमराह किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के दिन रात शिकायत के बाद भी विभाग अपनी लापरवाही और नाकामी पे सुधार नहीं कर पा रहे हैं। बता दे बीते 4-5 दिनों से जैजैपुर सब स्टेशन के अंतर्गत के ओड़ेकेरा फीडर में लगातार खराबी आ रहा हैं जिससे कारण 6-7 के ग्रामीण उपभोक्ताओं का जीना मुश्किल हो गया। बीते 4-5 दिन से सुधार के नाम पर बस जिम्मेदार जिला अधिकारी सहित स्थानीय अधिकारी के द्वारा आश्वासन ही दिया जा रहा है। जबकि यह समस्या कोई नई नहीं हैं बीते 2-3 वर्ष से यहाँ की स्थिति जस के तस बनी हुई जिसका ख़ामियाज़ा हर साल ग्रामीण इलाकों हज़ारों उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा हैं।

बता दें जिले के जैजैपुर सब स्टेशन के ओड़ेकेरा फ़ीडर में लगातार दो तीन वर्षों से बिजली गुल की समस्या लोग बेहद परेशान हैं। बेवजह बिजली कटौती में सुधार के नाम पर बिजली विभाग के स्थानीय जिम्मेदारों के द्वारा सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर उपभोक्ता एवं आला अधिकारियों के समक्ष वाहवाली लूट रहे। जबकि यहाँ की ज़मीनी हकीकत का आलम ये है की हल्की फुल्की हवा बारिश होने पर रात भर और दिन भर बिजली गुल रहती है। गर्मी का मौसम हो तो ओवरलोडिंग और लोड सेटिंग के नाम पर घंटों घंटों भर बिजली कटौती किया जाता है। जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं क़ीमती दिन चरिया पर पड़ता है। जिसका बिजली विभाग को कोई सरोकार नहीं। ताज़ूब की बात यह है की बिजली विभाग के जिम्मेदारों को ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का लगातार शिकायत मिलने के बावजूद विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर उसका निस्तारण सुधार ना हो पाना लोगों के मानों में रोष और आक्रोश को दिन ब दिन पैदा कर रहा है।

जैजैपुर सब स्टेशन के सभी फीडर में से ओड़ेकेरा फीडर का कनेक्शन रहता है खराब

आप सभी को जान कर हैरत होगा की जैजैपुर सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सभी फीडर का बिजली कनेक्सन में फाल्ट आने पर सुधार कार्य कराकर विद्युत सप्लाई चालू करा दिया जाता है तो वही ओड़ेकेरा फीडर बीते दो-तीन साल से गर्मी या बरसात में लाईन का खराब होने पर घंटों घंटों तक सुधार नहीं हो पाता है और कहीं रात के समय बिजली सप्लाई ख़राब हो जाए तो यहाँ के ग्रामीणों का भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। सप्लाई ख़राब होने ट्रिपिंग आने और ब्रेकडाउन के नाम पर दिन रात भर बिजली बंद रहने का आरोप उपभोक्ता लगा रहे हैं।

जिसका सुधार हो पाना भी संभव नहीं रहता है। ओड़ेकरा फ़िटर के उपभोगताओं कहना है यह समस्या बीते कई वर्षों से चल रहा हैं जिसका समाधान आज तक नहीं किया जा रहा है, बिजली विभाग के कर्मचारीयों के द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ दिखावा करने का भी आरोप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों लगा रहे हैं। बीते दिनों मौसम ख़राब होने के कारण 4-5 दिन ओड़ेकेरा, बहेराडीह, जुनवानी, गाड़ामोर, कुटराबोड़, छिर्राडीह इत्यादि गांव के उपभोक्ता बेहद परेशान और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जिसके कारण लोगों के चेहरे पर स्थानीय बिजली विभाग के प्रति नाराजगी साफ़ दिखाई दे रहा है।

जिंदल कंपनी की कुल्हाड़ी और माताओं का आँचल : नागरमुड़ा में आधी रात को 'जल, जंगल और ज़मीन' के लिए मातृशक्ति ने भरी हुंकार

रायगढ़/मूक पत्रिका

जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब एक माँ अपनी संतानों के भविष्य को लेकर अक्सर जागती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में स्थित नागरमुड़ा गांव में भी बुधवार की आधी रात को कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। यह लड़ाई सिर्फ पेड़ों को बचाने की नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई थी उस आजीविका, जलस्रोत और सांस्कृतिक पहचान की, जिसे ये ग्रामीण अपनी माँ मानते हैं।कोयला खदानों और औद्योगिक विस्तार के नाम पर जब मशीनों का शोर नागरमुड़ा के जंगलों का सीना चीरने की तैयारी कर रहा था, तब गाँव की महिलाओं ने, अपने छोटे-छोटे बच्चों की उंगलियां थामे, आधी रात को ही मोर्चा संभाल लिया।

क्या है पूरा मामला?तमनार विकासखंड के नागरमुड़ा गांव में हजारों पेड़ों की प्रस्तावित कटाई को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया हैआधी रात का संघर्षः बुधवार की रात जब ग्रामीणों को पेड़ों की कटाई की तैयारी की भनक लगी, तो महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों का हुजूम जंगल की ओर निकल पड़ा।

?कंपनी की टीम की वापसीः भारी विरोध को देखते हुए कंपनी प्रबंधन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और उनकी टीम बैरंग लौट गई।प्रशासन और पुलिस बल पर सवालः खबर के अनुसार, कंपनी प्रबंधन का कहना था कि वे केवल पहले से कटे हुए पेड़ों को उठाने आए थे। लेकिन ग्रामीणों का तीखा सवाल है कि यदि मंशा सिर्फकटे पेड़ उठाने की थी, तो आधी रात को प्रशासन और पुलिस टीम की क्या आवश्यकता पड़ गई? जंगल हमारे लिए केवल पेड़ों का समूह नहीं है, यह हमारी आजीविका, जलस्रोत, पर्यावरण और हमारी सांस्कृतिक पहचान का मूल आधार है।÷ ङ्क विरोध कर रहे ग्रामीण

लुभावने वादों के बीच अडिग मातृत्व और एकता?अक्सर विकास की अंधी दौड़ में सबसे ज़्यादा कीमत ज़मीन से जुड़े लोगों को चुकानी पड़ती है। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर में यह भी दावा किया गया है कि कंपनी प्रबंधन (जिंदल कंपनी) द्वारा कटाई का काम निकालने के लिए क्षेत्र के कुछ युवाओं को गुमराह करने का प्रयास किया गया। उन्हें नकद राशि, बस की व्यवस्था और चंद्रपुर में 'बकरा पार्टी' का लालच दिया गया। किंतु, गाँव की मातृशक्ति और जागरूक नागरिकों के सामने ये सब चालें धरी की धरी रह गईं। महिलाओं का स्पष्ट कहना था कि यदि इसी तरह जंगल खत्म होते रहे, तो आने वाली पीढ़ियों के सामने जल संकट, प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी।

विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण क्यों है ज़रूरी? तमनार क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में कोयला खदानों और बड़े औद्योगिक संयंत्रों का केंद्र बन चुका है। इसके कारणः

बड़े पैमाने पर वन भूमि का अधिग्रहण हुआ है और लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं।

अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता प्रभावित हो रही है और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं।

भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है और स्थानीय जलस्रोत सूख रहे हैं।

तापमान में वृद्धि, प्रदूषण और वर्षा चक्र में बदलाव जैसी गंभीर

जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सिग्नल चौक बेमेतरा में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ग्राम नकटी में 85 घरों को तोड़े जाने के विरोध में सिग्नल चौक, बेमेतरा में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया ग्राम नकटी में 85 परिवारों के मकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई के विरोध में सिग्नल चौक, बेमेतरा में जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि विष्णु देव के कुशासन सरकार ने गरीबों के आशियाने उजाड़ने का काम कर रही है, जो पूरी तरह अमानवीय और जनविरोधी है। बिना उचित पुनर्वास और मुआवजा दिए 85 परिवारों को बेघर करना अन्यायपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी।उन्होंने सरकार से मांग की कि ग्राम नकटी के प्रभावित सभी परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा, वैकल्पिक आवास एवं सम्मानजनक पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए तथा इस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि प्रभावित परिवारों को शीघ्र न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पूरे जिले में उग्र आंदोलन करेगी। इस अवसर पर मंगत साहू प्राणीश चौबे प्रांजल तिवारी झम्मन बघेल हरीश साहू रश्मि मिश्रा शकुंतला साहू राजू साहू सुमन गोस्वामी रवि रजक ललित विश्वकर्मा मनोज शर्मा दीपक दिनकर जोगेन्द्र छाबड़ा मिथलेश वर्मा मिन्टा नामदेव प्रकश ठाकुर राम ठाकुर जावेद खान द्वारिका तिवारी प्रतीक दुबे नारायण छाबड़ा महेंद्र साहू निलेश वैष्णव चितरेन वर्मा मनीष परिहार राजेश नवरंगे कोमल पुरी गोस्वामी लोकराम साहू आरिफ भाटिया लव कुमार गौरीशंकर शर्मा भीखम साहू कमल साहू शुभम सोनी सहित युवा कांग्रेस, एनएसयूआई बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

सिविल अस्पताल मे 27 वर्ष के युवक प्रदुम शर्मा की मौत, ओ टी इंचार्ज की भूमिका जाँच के घेरे

खरसिया/मूक पत्रिका

सिविल अस्पताल खरसिया मे 27 वर्ष के युवक प्रदुम शर्मा की मौत,ओ टी इंचार्ज की भूमिका जाँच के घेरे मे ऑपरेशन के बाद युवक की मौत से मचा था बवाल जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब नहीं आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तय होगा की इलाज मे लापरवाही हुई है या नहीं परन्तु इस मामले मे ओ टी इंचार्ज की भूमिका भी जाँच योग्य है

ओटी इंचार्ज की भूमिका और जिम्मेदारी-ऑपरेशन थिएटर में साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण ओ टी इंचार्ज को देखना होता है क्या आपरेशन के वक्त किसी संक्रमण का शिकार तो नहीं युवा युवक क्या सभी सर्जिकल उपकरण सही थे या इन्फेक्टेड थे जाँच का विषय है.

क्या ओ टी इंचार्ज की लापरवाही के कारण मरीज को कोई संक्रमित उपकरण का इस्तेमाल किया गया है यह जाँच का विषय है ओ टी इंचार्ज ने परिजनों को समय पर जानकारी नहीं दिया जिससे हालत गभीर हुई और युवक की मौत हुई मामले मे जांच जारी है पर इस गंभीर मामले मे डॉक्टर दोषी या ओ टी इंचार्ज की लापरवाही का नतीजा एक 27वर्षीय युवक प्रदुम शर्मा को मौत के रूप मे मिला

रायगढ़ को 'निगल' रहा अडानी! कोयला, खदान और रेल लाइनों के जाल में उलझता जा रहा जिला, हर तरफउठ रहे विरोध के स्वर

रायगढ़/मूक पत्रिका

ऊर्जा धानी के नाम से मशहूर रायगढ़ जिला अब बड़े औद्योगिक घरानों, विशेषकर अडानी समूह की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की जकड़ में आता दिख रहा है। जिले के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे प्रोजेक्ट्स और उनके भारी विरोध को देखकर अब स्थानीय लोगों की जुबान पर एक ही बात है– ऐसा लग रहा है मानो अडानी पूरे रायगढ़ को निगल रहा है। एक तरफ नई खदानों के लिए जमीनें छीनी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ कोयला परिवहन के लिए रेलवे लाइनों का जाल बिछाकर शहर की सांसें घोंटी जा रही हैं।

पेलमा खदानः विस्थापन का डर और औपचारिकता बनी जनसुनवाई

तमनार ब्लॉक के पेलमा में एसईसीएल और अडानी के संयुक्त उपक्रम वाले 15 एमटीपीए क्षमता के ओपनकास्ट कोल माइन प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। 8 जून को हुई जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था। स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, जंगल और आजीविका छिनने का डर सता रहा है। ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि उन्हें विकास के नाम पर विस्थापन मंजूर नहीं है, लेकिन उनकी आवाजें फाइलों में दबती नजर आ रही हैं। वहीं, कोरबा वेस्ट पावर प्लांट का विस्तार भी पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद अपनी राह पकड़ चुका है।

कोतरा रोड और गेजामुड़ा: बिना मुआवजे और सहमति के मनमानी-केवल खदानें ही नहीं, इन खदानों से कोयला ढोने के लिए बन रही रेलवे लाइनें भी शहर के लिए नासूर बन गई हैं। कोतरा रोड स्थित रेलवे की चौथी लाइन और कॉरीडोर का काम इसका जीता-जागता उदाहरण है। यहां किसानों की जमीनें अधिग्रहित कर ली गईं, लेकिन मुआवजे के नाम पर उन्हें या तो कौड़ियों के भाव पैसे थमाए जा रहे हैं या फिर अब तक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। गेजामुड़ा में भी रेलवे लाइन के लिए बिना किसानों की सहमति के जबरन काम शुरू करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते लोग मशीनों के सामने आकर काम रुकवाने को मजबूर हैं।

धूल, जाम और बदहाल व्यवस्था से पिसती जनता-ठेकेदारों की मनमानी का आलम यह है कि बिना उचित सर्विस रोड बनाए कोतरा रोड का काम चालू कर दिया गया है। इससे शहर का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है। जरा सी बारिश में अंडरब्रिज में पानी भर जाता है, व्यापारियों का धंधा चौपट हो रहा है और आम आदमी रोज जाम की चक्की में पिस रहा है। इसके साथ ही, रिहायशी इलाकों के बीच से गुजरने वाली इन कोयला लाइनों से उड़ने वाली धूल ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।

क्या कॉरपोरेट के दबाव में है प्रशासन?इन सभी मामलों में सबसे निराशाजनक भूमिका* स्थानीय प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की रही है। आम जनता और किसानों की जायज आपत्तियों का समाधान निकालने के बजाय, अधिकारी अक्सर बिना सहमति बनाए काम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा महकमा कॉरपोरेट हितों को साधने में लगा हुआ है।

आखिर यह कैसा विकास है जो स्थानीय लोगों को ही उजाड़ कर किया जा रहा है? अगर हालात यही रहे और प्रशासन ने जनता की नहीं सुनी, तो वह दिन दूर नहीं जब रायगढ़ का अपना वजूद ही इन औद्योगिक चिमनियों और मालगाड़ियों के धुएं में कहीं खो जाएगा।

बेमेतरा जिला जेल के 500 मीटर दायरे को 'नो ड्रोन फ्लाई जोन' घोषित, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला जेल बेमेतरा की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जेल परिसर के 500 मीटर के दायरे को आगामी आदेश तक 'नो ड्रोन फ्लाई जोन' घोषित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, जेल मुख्यालय, अटल नगर रायपुर से प्राप्त निर्देशों के पालन में यह निर्णय लिया गया है। जिला जेल बेमेतरा एकांत क्षेत्र में स्थित होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्य दीवार के ऊपर से प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने की घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में ड्रोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने और बंदियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

आदेश के तहत जिला जेल बेमेतरा की सीमा से 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा ड्रोन का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित

महापौर की भतीजी अंजू चौहान ने पति ऐश्वर्य चौहान के साथ विवाह पंजीयन के लिए नगरनिगम में किया आवेदन

रायगढ़/मूक पत्रिका

नगर निगम कार्यालय में विवाह पंजीयन कराने के उद्देश्य से महापौर जीवर्धन चौहान की भतीजी अंजू चौहान अपने पति ऐश्वर्य चौहान के साथ पहुंचीं। दोनों ने विवाह पंजीयन रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर नियमानुसार विवाह पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तथा आवश्यक दस्तावेज जमा किए। आवेदन प्राप्त होने के बाद निगम प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।नगर निगम में विवाह पंजीयन की प्रक्रिया शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न की जाती है। आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।यह प्रमाण पत्र विवाह का वैधानिक दस्तावेज होता है, जिसका उपयोग विभिन्न शासकीय एवं निजी कार्यों में किया जाता है।नगर निगम प्रशासन ने बताया कि विवाह पंजीयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। प्रतिदिन कई नागरिक विवाह पंजीयन के लिए निगम कार्यालय पहुंचकर आवेदन प्रस्तुत करते हैं। निर्धारित समय-सीमा में दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

इस दौरान निगम कार्यालय में विवाह पंजीयन की प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न हुई तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन स्वीकार कर आगे की कार्रवाई की गई।

पीएम सूर्य घर योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 1.5 लाख लेकर वेंडर फरार

बरमकेला/मूक पत्रिका

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए कर्ज का जाल बन गई है। विकासखंड बरमकेला के ग्राम गौरडीह निवासी भीमसेन पटेल के साथ 1.5 लाख रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भीमसेन पटेल ने 2 मई 2026 को पीएमसूर्य घर योजना के तहत वेंडर 'राहुल अग्रवाल-रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन' के माध्यम से सोलर पैनल के लिए आवेदन किया था। बैंक से लोन लेकर 1,50,000 रुपये सीधे वेंडर के खाते में ट्रांसफर कर दिए गये, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने पर भी न तो सोलर पैनल लगा, न ही कोई सामग्री भेजी गई। परेशान होकर भीमसेन ने 9 जून 2026 को सीएसपीडीसीएल के सहायक अभियंता, बरमकेला को लिखित शिकायत देकर वेंडर पर ब्लैकलिस्ट करने और ईएमआई रोकने की मांग की है। शिकायत दर्ज होने के बाद वेंडर राहुल अग्रवाल ने आनन-फानन में भीमसेन के घर कुछ सामान भेजा और काम आधा-अधूरा छोड़कर फिर फरार हो गया।

अब किसान भीमसेन को बैंक की ईएमआई भी पटानी पड़ रही है और बिजली का बिल भी भरना पड़ रहा है। 'मुफ्त बिजली' का सपना दिखाकर किसान को कर्ज और अंधेरे में धकेल दिया गया। सोलर से एक यूनिट बिजली नहीं मिली, लेकिन लोन का बोझ और बिजली विभाग का बिल दोनों चालू हैं।

अधिकारी भी कह रहे वेंडर की गलती-शिकायत के बाद वेंडर ने पीड़ित के घर सिर्फ सामान गिरवाया और काम आधा-अधूरा कर शेष कार्य सामान आने के बाद करने की बात कही। जबकि हकीकत में घर में अंधेरा कायम है और वेंडर गायब है। अधिकारी यह कह रहे हैं कि कागजों में काम होना गलत है ऐसे में पीड़ित को संबंधित पोर्टल पर आनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहिए।

क्या कहते हैं गदाधर सिदार, एई बिजली विभाग बरमकेला-पीएम सूर्य घर योजना में वेंडर के द्वारा सारा सिस्टम लगता है। इसमें बिजली विभाग सिर्फ आवेदक के सोलर पैनल सही लगा या नहीं इसका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करता है। भीमसेन पटेल मामले में वेंडर की लापरवाही है। आपको वेंडर के विरुद्ध पोर्टल में आनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। इसमें बिजली विभाग की कोई भूमिका नहीं है।

लैलूंगा की भगवती चंद्रा को मिला उज्जवला योजना का गैस कनेक्शन

सीएम हेल्पलाइन बना आमजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम

रायगढ़/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री की जनकेंद्रित सुशासन व्यवस्था के तहत संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रही है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड में दर्ज एक शिकायत का शीघ्र निराकरण करते हुए पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। लैलूंगा नगर के संत कबीर वार्ड क्रमांक-7 निवासी श्री धनेश्वर ने अपनी पत्नी श्रीमती भगवती चंद्रा के नाम पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं होने पर उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई।शिकायत प्राप्त होते ही जिला खाद्य नियंत्रक कार्यालय तथा संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की गई। जांच में पाया गया कि आवेदिका के नाम पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन स्वीकृत हो चुका था, किंतु तकनीकी एवं प्रक्रियागत कारणों से उसका लाभ हितग्राही तक नहीं पहुँच पाया था। मामले की पुष्टि होने के बाद खाद्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पात्रतानुसार हितग्राही को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया। इसके साथ ही शिकायत का संतोषजनक निराकरण कर प्रकरण का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। गैस कनेक्शन प्राप्त होने के बाद हितग्राही श्री धनेश्वर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी समस्या का समयबद्ध समाधान हुआ और उन्हें शासन की योजना का लाभ सहज रूप से प्राप्त हो सका। यह प्रकरण दर्शाता है कि सीएम हेल्पलाइन 1076 शासन और आमजन के बीच प्रभावी संवाद का सशक्त माध्यम बन चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुँच रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।